● वर्ष-4
● अंक-165
रायपुर, बुधवार
19 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» बच्चों से लालच देकर कोई काम ....

छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू

देर रात तक खुलेंगी दुकानें

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क

■ छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत

1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वत: शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।

पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा।

निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे। पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत

अहमदाबाद। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने फिर से अपना परचम लहरा दिया है। पार्टी ने 68 नगरपालिका में से 60 पर प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं, कांग्रेस को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से 15 नगरपालिका छीन ली हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी को दो नगरपालिकाओं में जीत मिली है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव पहली बार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण लागू होने के बाद हुए हैं। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ था। मंगलवार को मतगणना के बाद भाजपा 60 नगरपालिकाओं और तीन तालुका पंचायतों में स्पष्ट विजेता बनकर उभरी। कांग्रेस केवल देवभूमि द्वारका जिले की सलाया नगरपालिका सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं, अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। जूनागढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 44 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। तालुका पंचायत में भाजपा ने 55 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 सीटों पर सफलता मिली। गुजरात में रविवार को जूनागढ़ नगर निगम, 66 नगर पालिकाओं और तीन तालुका पंचायतों में मतदान हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर की मनसा नगर पालिका में भी भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। यहां 20 में से 19 सीटों पर भाजपा और और एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है।

भाजपा के 213 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, जूनागढ़ नगर निगम चुनाव में 44.32 फीसदी मतदान हुआ। नगर पालिकाओं के चुनाव में 61.65 फीसदी, जबकि तालुका चुनावों में 65.07 फीसदी मत पड़े। स्थानीय निकायों की 213 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया,

क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस और अन्य दलों के हटने के बाद केवल भाजपा के उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। इनमें जूनागढ़ निगम की आठ सीटें भी शामिल हैं।

परिणामों में दलों की स्थिति

भाजपा को 1403 सीटें, कांग्रेस को 260, समाजवादी पार्टी को 34, आम आदमी पार्टी को 28, बहुजन समाज पार्टी को बसपा को 19 और निर्दलीयों को 151 सीटों पर जीत मिली है।

ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सीटें

गुजरात में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। इसके अलावा नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों सहित स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। रविवार को कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गरमागरमी के मामले भी देखे गए।

सलाया में नहीं खुला भाजपा का खाता

भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बावजूद द्वारका के सलाया नगर पालिका में उसका खाता नहीं खुल। यहां आम आदमी पार्टी को 13 जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आईं।

प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब, चौतरफा जाम

कतर का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनेगा भारत

नईदिल्ली। कतर के अमीर भारत के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। कतर के भारत से संबंध कैसे हैं इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त शेख तमीम बिन हमद अल थानी के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कतर के अमीर के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के लिए कतर कहां है। कतर के अमीर जैसे ही भारत पहुंचे। वैसे ही भारत के विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत और कतर के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों ने करार किए।

दोनों देशों के बीच कई एमओयू भी साइन हुए। विदेश मंत्रालय की ओर से इसको लेकर जानकारी भी दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-कतर, गहरे और पारंपरिक संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी ने आज हैदराबाद हाउस में व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान देने और भारत-कतर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने तय किया कि वो कैसे दोनों देशों को आगे एक साथ ले जाएंगे और भारत कतर संबंधों को और मजबूत करेंगे।

भारत और कतर के बीच दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौता भी हुआ जिसकी घोषणा हैदराबाद हाउस में हुए समझौतों के दौरान की गई।

प्रमुख समाचार

टिप्पणी के लिए शुभेंदु के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा विपक्ष के नेता (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को कथित तौर पर मुसलमानों की सरकार कहने के लिए विशेषाधिकार

प्रस्ताव पेश किया गया। सोमवार को बंगाल विधानसभा से निलंबित किए गए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य के मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्पीकर बिमान बंदोपाध्याय ने कहा, यह सदन की अवमानना का मामला है। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। निलंबित किए जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। भाजपा विधायक ने कहा, हिंदू समुदाय की वकालत करने के लिए हमें अपने निलंबन पर गर्व है... यह मुल्लाओं की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, अंसारुल बांग्ला की सरकार है, कश्मीरी आतंकवादियों की सरकार है। मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू विरोधी सरकार है।

सत्येंद्र जैन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मिली मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आज आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। ईडी अब राष्ट्रपति

की मंजूरी की जानकारी देते हुए एक नया पूरक आरोपपत्र अदालत में दाखिल करेगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी थी। ईडी की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। बता दें कि जांच एजेंसी ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 से 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी।

सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की उच्च स्तरीय बैठक

रियाद। रूस और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपसी संबंधों को सुधारने और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू की। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सऊदी अरब में मुलाकात की। इसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को

रुबियो भी शामिल हुए। दोनों देशों के अधिकारियों ने अपने द्विपक्षीय संबंध सुधारने और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के रास्ते पर काम करने पर सहमति जताई। ट्रंप प्रशासन ने रूसी अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक करने के लिए सहमति देकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कुछ हद तक जीत दिला दी है। रूस ने ही 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। इस बैठक में शामिल होने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, जिससे यूक्रेनी नेता भावना आहत महसूस कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पत्रकारों को बताया कि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि एक परामर्श तंत्र बनाएंगे, जो दोनों देशों के संबंधों में पैदा होने वाली समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा।

समीक्षा बैठक में अमित शाह ने उमर की नाराजगी दूर की!

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में केंद्र शासित प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। आज की

बैठक की खास बात यह रही कि इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया गया। हम आपको बता दें कि पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद अब कानून-व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस बारे में मुख्यमंत्री के सलाहकार ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि निर्वाचित सरकार के मुखिया को कानून व्यवस्था संबंधी बैठकों में नहीं बुलाया जाना गलत है। संभवत: मुख्यमंत्री की उस नाराजगी के बाद ही उन्हें इस बैठक में बुलाया गया। नॉर्थ ब्लॉक में जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।

महाकुंभ मेले का एक्सटेंशन नहीं, 26 को समापन

महाकुंभ नगर (प्रयागराज)। इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैली है कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार और मेला व जिला प्रशासन की ओर से मेले का एक्सटेंशन करते हुए इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मांदड़ ने ऐसी अफवाहों का सिरे से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नितांत अफवाह है। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है, वह मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होगा और तब तक जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी के सुगम आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। मेले की डेट के एक्सटेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों पर डीएम ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

शिवसेना के 20 विधायकों की सुरक्षा घटाने पर महायुति में तकरार!

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध के दावों में नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्टस की माने तो सीएम फडणवीस के गृह विभाग ने 20 से अधिक शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में बदलाव किया। उनकी सुरक्षा को वाई+ श्रेणी से घटाकर सिर्फ एक कांस्टेबल पर कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य शिवसेना नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली गई।

हालांकि, गृह विभाग द्वारा भाजपा और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ नेताओं की सुरक्षा भी वापस लेने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार के इस कदम पर ना तो शासन ने कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही विधायकों ने कोई बयान जारी किया है।

एक दूसरे से आगे निकलने की होड़

महाराष्ट्र की राजनीति में यह घटना महायुति सरकार में भागीदारों के बीच एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ का हिस्सा है। सोमवार को शिंदे ने शिवसेना के उदय सामंत द्वारा आयोजित उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, जबकि फडणवीस ने जनवरी में ऐसी ही एक बैठक की थी। शिंदे की यह समीक्षा बैठक सामंत द्वारा भेजे गए एक पत्र के कुछ दिन बाद हुई। इससे ये तो साफ हो रहा है कि राजनीति में कुछ तो हलचल है।

किसके सुरक्षा कवर में हुआ बदलाव?

बात अगर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की करें तो अक्तूबर 2022 में शिंदे के सीएम बनने के बाद, जिन 44 विधायकों और 11 लोकसभा सदस्यों ने शिंदे का समर्थन किया था, उन्हें

वाई+ सुरक्षा कवर दिया गया था। लेकिन अब मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी विधायकों की सुरक्षा घटा दी गई है। कई पूर्व सांसदों से भी सुरक्षा वापस ले ली गई है। इनमें भाजपा और राकांपा के कुछ नेता, शिवसेना से जुड़े लोग, और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

भुगतान पर सुरक्षा का प्रस्ताव

अंबानी परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों को, जैसे कि अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सलमान खान को, भुगतान के आधार पर वर्गीकृत सुरक्षा दी गई है। इससे साफ है कि भाजपा और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद के कारण राज्य की राजनीति में कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जिनमें सुरक्षा कवर से लेकर मंत्रालयों के नियंत्रण तक कई पहलू शामिल हैं।

रायगढ़-नासिक विवाद पर प्रकाश

रायगढ़ और नासिक में विवाद को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच शुरू हुआ गतिरोध अब बढ़ता जा रहा है। यह विवाद पहले रायगढ़ और नासिक के लिए संरक्षक मंत्री पदों को लेकर था, जो अभी भी अनसुलझा है। सीएम फडणवीस एनसीपी नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया था। इस विवाद से शिंदे की नाराजगी साफ सामने आ रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पार्टी से कोई इस पद को संभाले। इसके बाद, इस विवाद ने और क्षेत्रों में भी बढ़त दिखाई है।

विवादित नियुक्तियां और बदलाव

फडणवीस को एक महत्वपूर्ण पद पर नामित किया गया था, लेकिन शिंदे को महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बाहर रखा गया था। इसके बाद नियमों में बदलाव किया गया, ताकि शिंदे को इसमें शामिल किया जा सके। इसी तरह, एमएसआरटीसी का अध्यक्ष एक नौकरशाह को नियुक्त किया गया, जबकि हाल के दिनों में परिवहन मंत्री इस पद पर थे।

शिंदे और फडणवीस की बैठकें

इसके साथ ही एक पहलू ये भी है कि पिछले महीने, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नासिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक छोड़ दी थी, जो फडणवीस द्वारा बुलाई गई थी, और बाद में उन्होंने खुद इस विषय पर अपनी समीक्षा बैठक की। हाल ही में, शिंदे ने मंत्रालय में एक नया डिप्टी सीएम का मेडिकल एड सेल स्थापित किया और अपने करीबी सहयोगी को इसका प्रमुख नियुक्त किया। यह पहली बार है जब किसी डिप्टी सीएम ने सीएम रिलीफ फंड सेल के बावजूद ऐसा सेल स्थापित किया है। इस बात से फडणवीस के समर्थकों में भी बातें तेज है।

मामले में अधिकारियों का कहना है कि सीएम और डिप्टी सीएम की समान विभागों पर समीक्षा बैठकों के कारण दोहराव हो रहा है। एक पूर्व अधिकारी ने बताया ने तकनीकी रूप से, डिप्टी सीएम के पास कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई विशेष अधिकार नहीं हैं। शिंदे की समीक्षा बैठकें दिखावे के लिए हो सकती हैं, क्योंकि आखिरी निर्णय तो सीएम के पास ही होते हैं।

राजनांदगांव कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

पार्टी पर आंतरिक षड्यंत्र और उपेक्षा का लगाया आरोप

राजनांदगांव। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष और जिला साहू समाज के अध्यक्ष भागवत साहू ने कांग्रेस पार्टी पर आंतरिक षड्यंत्र और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया था। भागवत साहू ने आज प्रेस क्लब में प्रेवासर्ता लेकर संगठन पर कई आरोप लगाए। वर्तमान में जिला पंचायत चुनाव में हारने के बाद पार्टी द्वारा कोई सहयोग नहीं करने की बात भी कही।

भागवत साहू ने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 03 टेरेसरा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। इसके विपरीत शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ नेताओं ने मिलकर साजिशन उनकी हार सुनिश्चित की।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए समर्पित होकर काम किया। बावजूद इसके पार्टी नेतृत्व ने उन्हें उपेक्षित किया। नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए भागवत साहू ने कहा कि डोंगरगढ़ के वर्तमान विधायक ने बागी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान पर गंभीर आरोप लगाया। उनका है कि इन नेताओं ने धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराकर बागी प्रत्याशी अंगेश्वर देशमुख को जिताने का काम किया।

भागवत साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, मैंने पार्टी नेतृत्व को समय रहते स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन मेरी बात को अनदेखा किया गया। मुझे भ्रमित किया गया और बागी प्रत्याशी को खुलकर समर्थन दिया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस घटना से कांग्रेस पार्टी की छवि को गहरा नुकसान हुआ है और बहुसंख्यक साहू समाज में असंतोष फैल गया है। भागवत ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी चरम पर है। कुछ नेता पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। मैं जब खुद न्याय पाने में असफल हूं तो कार्यकर्ताओं को कैसे न्याय दिला पाऊंगा? ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद पर बने रहना उचित नहीं है।

जशपुर जिला पंचायत की तीनों सीट हारी भाजपा
भाजपा मंडल अध्यक्ष भी नहीं जीत पाए पंच का चुनाव

जशपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आने लगे हैं। जशपुर में भाजपा को बड़ी हार मिली है। यहां बीजेपी जीत का खाता नहीं खोल पाई। क्षेत्र के तीनों जिला पंचायत सदस्य की सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है।

तीन जिला पंचायत सदस्य की सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें 2 में कांग्रेस और एक में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा के बागी गेंदबिहारी सिंह, क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस समर्थित आशिका कुजूर और क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस समर्थित मोनिका टोप्पो ने जीत दर्ज की है। वहीं बगीचा भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरीश आरिक भी पंच का चुनाव हार गए।

मंत्री के गढ़ में भाजपा की बड़ी हार, दो जिला पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस की जीत

मनेंद्रगढ़। जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। मनेंद्रगढ़ खड़गवां के दोनों जिला पंचायत क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है।

कांग्रेस की ममता सिंह और प्रिया मसराम ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 और 10 से जीत हासिल की है। क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत अध्यक्ष रही भाजपा समर्थित रेणुका सिंह और क्षेत्र क्रमांक 10 से जनपद अध्यक्ष रही भाजपा समर्थित सोनमति उर्रे को हार का सामना करना पड़ा।

देवर नगर पंचायत अध्यक्ष तो भाभी बनीं हारम ग्राम पंचायत की सरपंच

दंतेवाड़ा। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब आज 18 फरवरी मंगलवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। इस बार दंतेवाड़ा जिले के गीदम में देवर रजनीश सुराना ने नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है तो वहीं भाभी प्रमिला सुराना हारम ग्राम पंचायत की सरपंच चुन ली गई हैं। दोनों ने ही भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, इन दोनों की जीत पर गीदम में जश्न सा माहौल है। इस बड़ी जीत के बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष बने रजनीश और हारम की सरपंच बनीं भाभी प्रमिला ने कहा कि लोगों की सेवा का परिणाम है, कि हमें जीत मिली है, आगे भी जनता की सेवा और शहर-गांव के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने गीदम नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रजनीश सुराना को मैदान में उतारा था, उसने कांग्रेस के प्रत्याशी और अपने चचेरे भाई रविश को 200 से ज्यादा वोटों के अंतर से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रजनीश चुनाव जीत गए। रजनीश की भाभी और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष सुराना की पत्नी प्रमिला सुराना ने भी सरपंच का चुनाव दोबारा जीत लिया। प्रमिला ने वर्ष 2019 को ग्राम पंचायत हारम की सरपंच के लिए पहली बार चुनाव लड़ा था. तब वे जीतकर सरपंच बनी थीं। अब फिर से वर्ष 2025 के चुनाव में भाजपा ने टिकट दिया, चुनावी मैदान मे उतरीं और 268 वोट से चुनाव जीत गईं।

बीईओ पर शिक्षिकाओं के संगीन आरोप

■ केमेस्ट्री लैब को बनाया निजी कक्ष अधिकारी का आरोपों से इंकार

बालोद। बालोद जिले का एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में हैं।क्योंकि ये विद्यालय इन दिनों में जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल की शिक्षिका का लवर्स प्वाइंट बन चुका है। यहां पर पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं ने स्कूल में हो रहे इस अनैतिक कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई है।जिसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई।लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस गंभीर मामले में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।अभी भी ये स्कूल लव बर्ड्स के लिए घोंसला बना हुआ है।

बालोद जिले के बेलमांड उच्चतर माध्यमिक स्कूल की छह महिला शिक्षिकाओं ने एक शिकायत पत्र प्रशासन सहित विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा है।शिक्षिकाओं ने शिकायत की है कि उनके विद्यालय में विकासखंड जिला शिक्षाधिकारी अक्सर दौरा करते हैं।जब वो दौरे पर आते हैं तो स्कूल की एक शिक्षिका उनके साथ विद्यालय के लैब में घंटों प्राइवेट मीटिंग करते हैं।इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि अधिकारी और मैडम की मीटिंग में किसी भी तरह की खलल ना पड़े इसके लिए स्कूल के प्राचार्य लैब का कमरा उपलब्ध कराते हैं।इस मामले में शाला विकास प्रबंधन समिति का कहना है यदि किसी के साथ किसी का पर्सनल रिश्ता हो तो उन्हें दूसरी जगहें तलाश लेनी चाहिए।लेकिन विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती।

इन शिक्षिकाओं ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसंत बाघ पर जो आरोप लगाया है

वो बेहद संगीन हैं। महिलाओं के मुताबिक बसंत बाघ स्कूल में आने के बाद एक मैडम से मिलते हैं। इस दौरान स्कूल में पार्टी भी होती है।स्कूल के लैब को प्राचार्य ने अधिकारी और मैडम का प्राइवेट प्लेस बना डाला है। वहीं जब इन आरोपों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने स्कूल के प्राचार्य नरेश मंडावी से बात करनी चाही तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किसी भी तरह के बयान देने से मना कर दिया।हां ऑफ द रिकॉर्ड इतना जरुर कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है।मैं तो वही करता हूं जो किसी भी अधिकारी के आने पर प्राचार्य को करना चाहिए।वहीं विकासखंड शिक्षाधिकारी ने खुद के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया।

बीईओ बसंत बाघ ने बताया आरोप बेबुनियाद है शिक्षकों की आपसी लड़ाई में इस तरह बदनाम करने की साजिश है। ऐसा संभव नहीं है कि जिम्मेदार पद में रहते हुए स्कूल में ये सब हो। विभागीय जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब मीडिया बेलमांड स्कूल पहुंची तो शिक्षिकाओं ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया।शिक्षिकाओं का कहना था कि यदि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोला तो अधिकारी उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहीं मामले में ये भी जानकारी मिली है कि बालोद के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायत करने वाली शिक्षिकाओं को लीगल नोटिस भेजा है।

बालोद जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी डीपी कोसरे ने बताया कि ग्राम बेलमांड का मामला बेहद संवेदनशील है। इसके लिए जो शिकायत प्राप्त हुआ है उस पर जांच कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है। लेकिन उच्च अधिकारी के स्वास्थ्य में खराबी के वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। जैसे ही अधिकारी अवकाश से आएंगे मामले में जांच और उचित कार्रवाई की जाएगी।

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सत्या गांवरे के मुताबिक प्रबंधन समिति के सामने गंभीर मामला आया था। लेकिन जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने इसकी शिकायत विभाग स्तर पर कर दी है इसलिए सारा मामला अब जिला शिक्षा विभाग के पास है ।उनके द्वारा यदि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो शाला प्रबंध समिति और ग्रामीण न्याय की मांग करेंगे। क्योंकि यहां पर हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेने आते हैं ना की कोई गलत शिक्षा। बच्चों के भविष्य के लिए हम सब आगे आएंगे यदि किसी का किसी से कोई पर्सनल रिश्ता है तो उन्हें पर्सनल जगह पर मिलना चाहिए। ना कि किसी शिक्षा के मंदिर में और यदि कोई विशेष है तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है।

द्वितीय चरण में 20 फरवरी को बलरामपुर में होगा मतदान

83 हजार से भी अधिक मतदाता करेंगे अपने मतों का प्रयोग

बलरामपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत दूसरे चरण में मतदान की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिसके तहत दूसरे चरण में जनपद पंचायत बलरामपुर में मतदान होना है। जिसके अंतर्गत 20 फरवरी 2025 को सुबह 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक मतदान होगा। जिसके लिए 19 फरवरी को बलरामपुर मुख्यालय में बनाए गये स्ट्रांग रूम स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल बलरामपुर में सुबह 06 बजे से मतदान सामग्रियों का वितरण किया जाएगा।

गौरतलब है कि बलरामपुर जनपद पंचायत अंतर्गत कुल 80 ग्राम पंचायत है। जहां मतदाताओं की कुल संख्या 83 हजार 737 है। जिसके अंतर्गत 41 हजार 456 पुरुष मतदाता एवं 42 हजार 281 महिला मतदाता है। जिनके लिए 183 मतदान केन्द्र बनाये गये है। जहां 20 फरवरी को मतदान कराने के लिए 768 मतदान कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है।

पहले चरण में 86.39 प्रतिशत हुआ मतदान

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत पहले चरण में राजपुर, शंकरगढ़ व कुसमी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हुआ। जिले के तीनों जनपद पंचायतों में कुल 86.39 प्रतिशत् मतदान हुआ। जिसमें जनपद पंचायत राजपुर में 87.57 प्रतिशत, जनपद पंचायत शंकरगढ़ में

87.62 व जनपद पंचायत कुसमी में 84.21 प्रतिशत् मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी वर्गों बुजुर्गों, महिलाओं, युवा मतदाताओं के साथ नये मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

दूसरे चरण में मतदान तिथि को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत दूसरे चरण में 20 फरवरी 2025 को मतदान होना है। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत बलरामपुर में दूसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान तिथि संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। जिसके लिए मतदान तिथि गुरुवार 20 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत बलरामपुर क्षेत्र में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

मतगणना पर शुष्क दिवस घोषित

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 20 फरवरी 2025 को दूसरे चरण में मतदान होना है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने उक्त तिथि को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत दूसरे चरण में 20 फरवरी 2025 को मतदान होना है, इसके लिए बलरामपुर की मदिरा दुकान 18 फरवरी दोपहर 03 बजे से 20 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगी। उक्त अवधि में जनपद पंचायत बलरामपुर क्षेत्र स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सील बंद करने एवं मदिरा क्रय-विक्रय मादक पदार्थों का अवैध रूप से विनिर्माण/परिवहन/संग्रहण/ धारण पर पूर्णत: प्रतिबंध पूर्णत: बंद रहेगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सुपरवाइजर से कंपनी के कर्मचारियों ने की मारपीट

कोरबा। कोरबा में बालको थानांतर्गत मारपीट की एक घटना सामने आई है। लालघाट देसी शराब दुकान के सुपरवाइजर के साथ प्लेसमेंट एजेंसी ऑल सर्विस ग्लोबल प्रा.लि.कोरबा के करीब पांच कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित का नाम कमलेश गुप्ता है, जो तुलसी नगर का निवासी है। बातचीत के दौरान कमलेश ने बताया कि जब वह शराब दुकान के भीतर घुसा था। तब कर्मचारियों ने अकड़ दिखाने की बात कहते हुए गोदाम के भीतर ले गए और लात घूसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद जमीन पर लेटाकर जुतों से भी उसके साथ मारपीट की। सरेआम हो रही मारपीट की घटना मौके पर मौजूद लोग और कुछ कर्मचारियों ने भी देखा। इस घटना के बाद सभी शराब दुकान के कर्मचारी एकजुट हो गए हैं और कंपनी के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करने का मन बनाया है। पीड़ित ने बालको थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अपराध कायम कर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है।

दुर्ग पुलिस ने जयपुर से चार साल बाद ठग दबोचा

दुर्ग। सुपेला पुलिस ने चार साल से फरार चल रहे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर यह धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट सुपेला थाने में दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग पुलिस ने आरोपी को जयपुर मानसरोवर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज की है। भिलाई नगर के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आठ जून 2020 को पीड़ित प्रणय कुमार गांगुली ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज की थी। उसने वह शेयर को लेकर पत्राचार करता था। इस बीच वह कानपुर से आकर भिलाई में रहने लगा। जिसके बाद इस समय अवधि में पत्र नहीं मिल सका। जिसका फायदा उठाकर आरोपी बिमल शाह ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। उसके बाद उसने 70 लाख रुपये के शेयर, जिसकी वर्तमान कीमत 2 करोड़ 75 लाख रुपए को खरीदना बताकर उसे ट्रांसफर के लिए प्रकरण पेश किया।

दुर्ग में भाजपा की अध्यक्ष ने लोगों को कहा धन्यवाद

दुर्ग। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता से नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नगरपालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा ने आभार रैली निकालकर नगर के लोगों का आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष मीना वर्मा ने कांजी हाउस के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर रैली की शुरुआत की, उन्होंने सभी वार्डों के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस जीत का श्रेय सभी नगरवासियों को देते हुए सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया। दुर्ग जिले में 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं। जिसमे कुम्हारी, अहिवारा और अमलेश्वर हैं। जिसमें सबसे ज्यादा मतों से कुम्हारी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा ने कांग्रेस को रामप्यारी थनेश पटेल को 4 हजार 660 मतों से हराकर जीत हासिल की है। अहिवारा के निर्दलीय प्रत्याशी विद्यानंद कुशवाहा ने भाजपा के प्रत्याशी नटवर ताम्रकार को 2807 मतों हराया। वहीं अमलेश्वर में दयानंद सोनकर ने कांग्रेस के मोनू साहू को हराकर अध्यक्ष बने हैं।

हेलमेट लगाकर नहीं गए दफ्तर तो चालान कटना तय

जगदलपुर। जगदलपुर शहर में बढ़ते सड़क हादसों के बीच ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर मेगा अभियान चलाया है, ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत जगदलपुर के एसपी दफ्तर से की है, इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एसपी दफ्तर आने जाने वाले सभी कर्मचारियों की चैकिंग की इस दौरान जो कर्मचारी हैलमेट या बिना नंम्बर प्लेट की गाड़ी में मिला उनका चालान ट्रैफिक पुलिस काट रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में एकाएक सड़क हादसों में इजाफा होता जा रहा है, बताया जा रहा है कि अधिकतर हादसों की वजह तेज रफ्तार गाड़ी व हैलमेट नही लगाना है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में और तेजी लाते हुए सभी सरकारी दफ्तरों के अलावा शहर में भी इस तरह का चैकिंग अभियान चलाया जायेगा, इसके लिए बस्तर एसपी ने भी आदेश जारी कर दिए है, कि जितने भी पुलिस कर्मी है वे नियमित रूप से हेलमेट का उपयोग करके ही वाहन चलाएंगे, साथ ही इस नियम को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्यवाही भी किया जाएगा।

तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दो लोगों को कुचला

रायगढ़। रायगढ़ जिला मुख्यालय में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाईक सवार दो युवको अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में घटना स्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई वहीं दूसरा गंभीर हो गया था जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना स्थल पर ही करीब दो घंटे तक चक्काजाम किया। उक्त घटना जूटमिल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पुसौर ब्लाक के अंतर्गत आने वाले जकेला निवासी नितेश पोबिया 15 साल अपने साथी गोकुल किशन के साथ किसी काम के सिलसिले में शहर की तरफ आया था और वापस अपने गांव लौटते समय जब वह कांशीराम चौक के पास पहुंचा ही था कि ओडीसा की तरफ जा रहे बालू लोड़ ट्रेलर चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाईक सवार दोनों युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में बाईक चला रहे नितेश पाव भारी वाहन के चक्के में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

सरकारी कर्मचारियों की मनमानी पर सख्ती

स्कूल निरीक्षण में गैरहाजिर मिले 13 शिक्षक-कर्मचारी

■ शोकॉज नोटिस जारी

धमतरी। जिले में संचालित सभी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए कलेक्टर नम्रता गांधी ने सभी अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी क्रम में आज अपर कलेक्टर रीता यादव ने डॉ। शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। वे सुबह 10 बजे स्कूल परिसर में पहुंची और स्कूल में कार्यरत शिक्षकों तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान 13 शिक्षक-कार्यालयीन स्टाफ निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित नहीं मिले।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य पूनम पाण्डेय, व्याख्याता मनोज साहू, प्रदीप शर्मा,

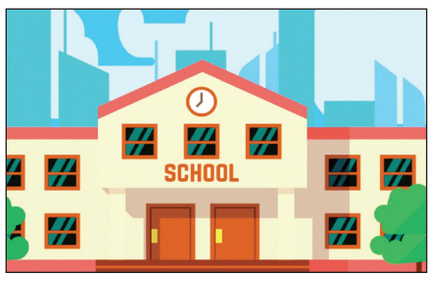

तृप्ति जाचक, कमलेश कुमार साहू, व्याख्याता एलबी रंजना साहू, भारती ठाकुर, ज्योति सोनकर, सहायक शिक्षक खोमेश्वरी, कुमारी नेहा वर्मा, सहायक ग्रेड 02 आनंद ठाकुर, सहायक ग्रेड 03 सरोज गुरूपंचायन और प्रधानपाठक सुभद्रा कश्यप अनुपस्थित रहे। कलेक्टर के निर्देश पर अनुपस्थिति सभी शिक्षकों और स्टॉफ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की शासकीय कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5।30 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी तरह शिक्षकों को स्कूलों में निर्धारित पालियों अनुसार समय पर पहुंचकर विद्यार्थियों को पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ।शोभाराम देवांगन स्कूल में निर्धारित समयों पर शिक्षकों और अन्य कार्यालय स्टॉफ की अनुपस्थिति से विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ा ही, साथ ही शिक्षा संबंधी अन्य कार्यों के संचालन में भी विलंब हुआ है। इस आधार पर अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने पीजी काउंसिलिंग पर लगाई रोक

चिकित्सा पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, अगली सुनवाई 25 को

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि वे सेवारत डॉक्टर हैं। 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। नियमों के अनुसार सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक तीन साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है, लेकिन काउंसिलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

दरअसल डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी

राजशेखर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इसमें बताया कि उन्हें मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसिलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। अधिकारियों ने सेवा अवधि की गणना कटऑफ तारीख से आगे बढ़ा दी, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को भी पात्र मान लिया गया। उन्होंने विभाग में इस गड़बड़ी की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारियों ने एक निजी उम्मीदवार को सेवारत श्रेणी में प्रमाणित किया है।

जांच में सामने आया कि सेवा अवधि की गणना 31 जनवरी 2024 के बाद तक बढ़ा दी गई। यदि कटऑफ तारीख का पालन किया जाता, तो वह उम्मीदवार पात्र नहीं होता। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने भी माना कि शिकायत सही लग रही है। हाई कोर्ट ने पाया कि निजी उम्मीदवार को कटऑफ तारीख के बाद सीट आवंटित की गई। हाईकोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिया कि यह आदेश केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। महाधिवक्ता को इस आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने निर्देश दिया गया है।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस को अब बोरिया बिस्तर बांधकर इटली चले जाना चाहिए : पुरंदर मिश्रा

रायपुर। चुनावी नतीजों के बाद विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निकाय के नतीजों और पंचायतों के रुझानों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा, बोरिया बिस्तर बांधकर कांग्रेस को इटली चले जाना चाहिए। पंजाब का दायित्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। हिमालय भी पास है, वही से तप करने निकल जाना चाहिए। पुरंदर मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा देने की ओर इशारा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ छोड़कर बैज को ओडिशा शिफ्ट हो जाना चाहिए। हार हुई, जनादेश स्वीकार करने के लिए होता है।

धमतरी जिला पंचायत की 6 में से 5 सीटों पर भाजपा की जीत

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भाजपा का जलवा है। धमतरी जिले की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समधी टीकाराम कंवर भी धमतरी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए हैं। उन्हें भाजपा की ओर से क्षेत्र क्रमांक 9 से प्रत्याशी बनाया गया था। इस क्षेत्र में पहले चरण में वोटिंग हुई थी, जिसमें टीकाराम कंवर ने उत्तम कुमार मरकाम को हराया।

इसके अलावा धमतरी जनपद पंचायत की 25 में से 18 और मगरलोड जनपद पंचायत की 23 में से 15 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा धमतरी जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के भरोसे का नतीजा बताया।

मुख्यमंत्री साय से रायपुर एवं बिलासपुर की नव निर्वाचित महापौर ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से उनके निवास पर रायपुर एवं बिलासपुर नगर निगम की नव निर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे एवं श्रीमती पूजा विधानी ने मुलाकात की। श्री साय ने उन्हें नव दायित्व के लिए बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दोनों ही नगर निगमों की जनता ने भाजपा सरकार के कार्यों पर अटूट विश्वास करते हुए पर अपना पूर्ण विश्वास भाजपा पर जताया है और दोनों ही शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। आप दोनों महापौर की जिम्मेदारी है कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तन्मयता से कार्य करें। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री साय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रगौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती (19 फरवरी) पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, उत्कृष्ट रणनीतिकार और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों, अनुशासित सेना और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राज्य की नींव रखी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य एवं राष्ट्रप्रेम आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों में भी अद्वितीय विजय प्राप्त की। उनकी रणनीति, सुशासन और लोकहितकारी नीतियाँ सदियों तक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, संकल्प और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनकी अमर गाथा भारत के युवाओं में राष्ट्रप्रेम और अदम्य उत्साह की भावना जागृत करती रहेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक 22 को

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 22 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष क्रमांक एम-5/20 में यह बैठक पूर्वान्ह् 11:30 बजे से होगी।

सारनाथ एक्सप्रेस 19 व 21 को रहेगी रद्द

रायपुर। परिचालनिक कारणो से गाड़ी संख्या 15160 / 15159 दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। 19 फरवरी को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस एवं 21 फरवरी शुक्रवार को छपरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

मुख्यमंत्री ने श्री गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, समाज सुधारक और प्रखर विचारक श्री गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि (19 फरवरी) पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गोखले जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बौद्धिक और नैतिक नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई पारी से पहले गंगा मैया का आशीर्वाद, विधायक राजेश मूणत ने विपक्ष को भी किया आमंत्रित

महाकुंभ के लिए नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ मेयर मीनल चौबे रवाना

रायपुर। नगर निगम रायपुर में 15 साल बाद भाजपा बड़ी जीत के साथ लौटी है। जिसे लेकर पार्टी में खुशी का माहौल है। अब नई पारी की शुरुआत करने से पहले नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे आज 40 से ज्यादा पार्षद के साथ महाकुंभ यात्रा के लिए रवाना हो चुकी है। कुल 150 लोग लग्जरी बस में प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में यह यात्रा हो रही है। उन्होंने यात्रा में विपक्ष को भी आमंत्रित किया।

विपक्ष को भी साथ ले जाएंगे : विधायक राजेश मूणत

विधायक राजेश मूणत मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को महाकुंभ लेकर जा रहे हैं। यहां कोई नगर निगम नहीं लेकर जा रहा है। हां लेकिन विपक्ष भी अगर आस्था के केंद्र में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उनको भी ले जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी जा रहे हैं। शुभ काम करने के पहले पूजा पाठ पद्धति से इसकी शुरुआत करते हैं। 60 पार्षद मी बनने जा रहे हैं। हम सब मिलकर प्रगति के मार्ग को आगे लेकर जाएं। कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ करने जा रहे हैं। शहर के विकास में सभी हम सहयोग देंगे। शहर का डेवलपमेंट करेंगे। इस आस्था के साथ हम महाकुंभ जा रहे हैं।

महाकुंभ से आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा : मीनल

महापौर मीनल चौबे मीडिया से बातचीत में कहा कि 15 वर्षों के बाद नगर निगम में भाजपा की सरकार आई है। बहुत प्रसन्न विषय है। सब की इच्छा थी कि पदभार ग्रहण के लिए महाकुंभ स्नान करने जाना है। हमारी इच्छा पूरा करने के लिए भाजपा संगठन से रमेश ठाकुर और राजेश मूणत को मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूं। विश्वास के साथ रायपुर शहर की जनता ने हमको चुना है। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे शहर का अच्छा विकास हम करेंगे।

व्हाइट हाउस में गंगजल छिड़कर शपथ लें : पुरंदर

पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से कहा कि विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में प्रयागराज जा रहे हैं। जितने पार्षद जीते हैं। सभी जा रहे हैं। उन पार्षदों में 1 के साथ 1 फ्री है। चारों विधानसभा के लोग जा रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि 15 साल से कूटनीति के कारण गंदे हुए व्हाइट हाउस में गंगाजल छिड़कर शपथ लें।

ज्ञात हो कि रायपुर नगर निगम में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 15 साल बाद महापौर पद पर कब्जा जमाया। महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने 1,53,290 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं रायपुर के 70 वार्डों में भी भाजपा का दबदबा दिखा, जहां 70 में से 60 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए।

भाजपा ने अबकी बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कार्टून के जरिए कसा तंज

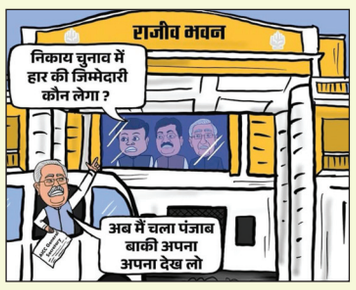

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस पर हमले के लिए कार्टून को एक जरिया बना लिया है। गाहे-बगाहे इन कार्टूनों के जरिए कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ पार्टी के आला नेताओं पर तंज कसती रहती है। अबकी बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कार्टून के जरिए तंज कसा है।

सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने कार्टून जारी कर कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आला नेताओं को निशाने पर लिया है। निकाय परिणाम के जारी होने से पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तत्काल प्रभाव से पंजाब की कमान सौंप दी थी। ऐसे में निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर पार्टी में मचे कश्मकश को उजागर किया है। बता दें कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब तक न तो दीपक बैज ने जिम्मेदारी ली है, और न ही नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने, जिन्होंने अंबिकापुर में चुनाव के दौरान अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने वाला बयान देकर राजनीतिक सनसनी पैदा करने के बाद बयान से पलटते हुए नगरीय निकाय चुनाव में अंबिकापुर क्षेत्र में सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहने का दावा किया था।

सीएम साय ने सैम की टिप्पणी पर साधा निशाना, बोले-

कांग्रेस अलगाववादियों और भारत के दुश्मनों के साथ खड़ी है

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की चीन के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम साय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विपक्षी पार्टी अलगाववादियों और देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने कथित तौर पर कहा था कि वह नहीं समझते कि भारत को चीन से कितना खतरा है और इसे अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। साय ने पूछा कि क्या पार्टी नेता को निष्कासित करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों और देश के दुश्मनों के साथ है। पार्टी के विदेशी विंग के प्रमुख पित्रोदा को शायद देश के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले अपनी नस्लवादी टिप्पणियों से भारतीयों का अपमान किया और अब वे विभिन्न मंचों पर भारत के बारे में बार-बार झूठा प्रचार कर रहे हैं।

सीएम साय ने कहा कि देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस की अघोषित नीति है। उन्होंने आगे दावा किया कि पित्रोदा के बयानों को उनके निजी विचार कहना कांग्रेस की पूर्व-निर्धारित नीति है। उन्होंने कहा कि पहले अपने नेताओं से बयान दिलवाकर देश के दुश्मनों को खुश करो और फिर उन्हें निजी टिप्पणी कहो।

भाजपा नेता ने दावा किया कि ये सभी बयान संबंधित देश (चीन) की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कांग्रेस के आधिकारिक समझौते के कारण दिए गए हैं। सीएम ने सवाल पूछा कि अगर कांग्रेस पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है तो क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए? अगर उन्हें निष्कासित नहीं किया जाता है तो यह साबित हो जाएगा कि ये बयान कांग्रेस के इशारे पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बैज पर फोड़ा

■ कहा- तुरंत हो संगठन में बदलाव

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद एक बार फिर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा चर्चा में हैं। निकाय चुनाव मतदान के बाद बागियों की घर वापसी पर सवाल उठाने वाले जुनेजा ने पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन में तुरंत बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है।

रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि संगठन कमजोर रहा है। निर्दलीय लोगों को बिठाने में पार्टी विफल रही, पोलिंग पांच बजे समाप्त हुई, और 18 लोगों को प्रवेश दें दिया गया, किसके बोलने से प्रवेश किया गया? ये सभी चुनाव हारने का कारण हैं।

इसके साथ ही उन्होंने संगठन में तत्काल बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर कहा कि न प्रदेश में पकड़ बना, न कुछ काम किया। दीपक बैज की कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि जो भी नए अध्यक्ष आएंगे, उनसे इस लिस्ट को निरस्त करने की माँग करेंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि संगठन में खरीद-फरोख्त की जांच के लिए जो मैंने पत्र लिख है, उस पर जांच होगी।

नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, बल्कि मौजूदा संगठन को हार मिलने की बात कहते हुए कुलदीप जुनेजा ने कहा कि चार चुनाव हार के बाद भी यदि इस्तीफ़ा मांगा जाए तो शर्म की बात है। नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है, दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है। कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जल्द होना जरूरी है।

वार्डों का सर्वांगीण विकास पार्षदों की प्राथमिकता में हो : साय

अटल विश्वास पत्र के वादों को पूरा करने में पार्षदों की भूमिका अहम

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के महापौर एवं पार्षदों से कहा है कि वार्डों का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं सहज रूप से मिल सकें। सभी पार्षद अपने वार्ड के लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भाजपा को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है, जो जनता के हमारी सरकार पर विश्वास को दर्शाता है। यह जीत संगठन के नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक के परिश्रम का परिणाम है। अब हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और अटल विश्वास पत्र में किए गए वादों को पूरा करना है। इसमें महापौर एवं पार्षदों की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि वे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि नगरीय निकायों के सभी महापौर और पार्षद अपने क्षेत्र में स्वच्छता, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जनता से लगातार संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करें अपने क्षेत्र में घूमकर समस्याओं को जाने इससे प्रशासनिक कसावट आएगी और विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने निवास पर दुर्ग एवं धमतरी नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कंधों पर है और उन्हें पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नगरीय निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत से प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार का संयोग बना है, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इन चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसमें 10 में से 10 नगर निगम, 49 में से 35 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में से 81 पर जीत हासिल की। इस अवसर पर विधायक श्री गजेंद्र यादव, धमतरी के नवनिर्वाचित महापौर श्री जगदीश रामू रोहरा, दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार सहित अन्य निकायों के पार्षदगण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश भर से निर्वाचित महापौर और पार्षदों का जत्थों के रूप में मुलाकात करने का क्रम लगातार जारी है। पिछले तीन दिनों में शताधिक पार्षद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया चीफ कौन? भूपेश ने दिया ये जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट चल रही है। कहा जा रहा है कि दीपक बैज से अध्यक्ष पद छीनकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है।

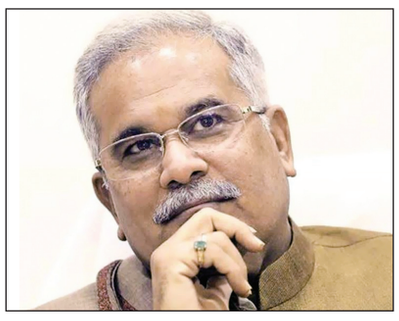

छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने की चर्चा पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा संगठन में नियुक्तियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का विशेषधिकार है। इस मामले में हम कोई बात नहीं करते हैं ना इसके लिए अधिकृत है। ये उनका विशेषाधिकार है। पार्टी जो फैसला करेगी वो शिरोधारी है।

बघेल ने उनको छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर कहा कि हाल ही में पार्टी ने उन्हें पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। ऐसे में एक समय में दो पद नहीं देंगे और ये उचित भी नहीं है।

दुर्ग के अम्लेश्वर में धर्मांतरण पर बवाल को लेकर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा विष्णुदेव साय सरकार में लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही है। यदि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो इसका मतलब ये हैं कि उसे रोकने में प्रदेश की सरकार विफल है।

बता दें कि सोमवार को दुर्ग के अम्लेश्वर में में धर्मांतरण के मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उनके घर को घेर लिया। वहां हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस मामले में बवाल होने के बाद दुर्ग पुलिस ने डॉक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

रायपुर नगर निगम के 7 वार्डों में मोदी और अटल विश्वास का जादू नहीं चल पाया

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। पर सात वार्ड ऐसे भी हैं जहां न तो मोदी मैजिक चला नहीं अटल विश्वास पत्र पर वोट पड़े। इन सात वार्डों में कांग्रेस के स्टार चमके और जनता ने यहां कांग्रेस का साथ दिया। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में बीजेपी ने 60 वार्डों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को महज 7 वार्डों में जीत से संतोष करना पड़ा। तीन निर्दलीय पार्षद भी यहां से चुनाव जीते हैं। पूर्व में महापौर पद की कुर्सी पर ऐजाज ढेबर का कब्जा था। बीजेपी की जीत के बाद रायपुर नगर निगम में अब मीनल चौबे महापौर बनेंगी।

जिन 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसमें से पांच पर कांग्रेस और दो पर भाजपा का कब्जा रहा। जिन सात सीटों पर कांग्रेस के 7 स्टारों ने जीत हासिल की है उसमें संदीप साहू, रोनिता जगत , दीपमणी साहू, शेख मुसीर, अर्जुमन ढेबर, रेणु जयंत साहू और जयश्री नायक शामिल हैं। जीतने वाले इन पार्षदों को स्टार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाजपा की लहर के बावजूद, इन वार्डों में कमल नहीं खिला। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 7 स्टारों में पांच महिला पार्षद शामिल हैं।

विजेताओं पर एक नजर

वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के संदीप साहू जीते: कांग्रेस के संदीप साहू वीर सावरकर वार्ड नंबर 1 से चुनाव मैदान में उतरे। संदीप के खिलाफ भाजपा ने विशाल पांडेय को मैदान में उतारा। यहां संदीप साहू 870 वोट से जीते। इस वार्ड में साल 2019 से भाजपा का कब्जा था ओर कमलेश वर्मा पार्षद थे।

वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस की रोनिता जगत जीतीं: रोनिता जगत को मनमोहन बक्शी वार्ड क्रमांक 23 से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। रोनिता के खिलाफ भाजपा ने कृष्णा भारती को चुनाव मैदान में उतारा। रोनिता जगत 128 मतों से जीत गईं। इसके पहले 2019 में भी इस वार्ड पर कांग्रेस का ही कब्जा था और प्रकाश जगत पार्षद चुने गए थे।

वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस की दीपमणी साहू बनी विजेता: वल्लभभाई पटेल वार्ड क्रमांक 24 से कांग्रेस ने दीपमणी साहू को उम्मीदवार बनाया। यहां से भाजपा ने राधिका साहू को मैदान में उतारा था। बीजेपी प्रत्याशी को कांग्रेस की दीपमणी साहू ने 152 वोट से हरा दिया। इस वार्ड में 2019 में कांग्रेस के ही मनीराम साहू पार्षद थे।

वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस के शेख मुसीर बने विजेता: शेख मुशीर को कांग्रेस ने हालदार अब्दुल हमीद वार्ड क्रमांक 35 से उम्मीदवार बनाया। भाजपा यहां दौड़ से बाहर नजर आई और निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अनीस निजामी यहां दूसरे स्थान पर रहे। निजामी को कांग्रेस के शेख मुसीर ने 1370 मतों से हराकर पार्षद की कुर्सी हासिल की। इस वार्ड में 2019 में भी कांग्रेस का कब्जा था और अनवर हुसैन पार्षद थे।

वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस की अर्जुमन ढेबर ने बीजेपी को हराया: कांग्रेस के पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर को वार्ड नंबर 45 से चुनाव मैदान में उतारा गया। यहां भाजपा की प्रीति परताले चुनाव मैदान में थी जिन्हें कांग्रेस की अर्जुमन ढेबर ने 2560 मतों से हराकर जीत हासिल की। इस वार्ड से 2019 में एजाज ढेबर पार्षद चुने गए थे जिन्हें बाद में महापौर बनाया गया था।

कांग्रेस की रेणु जयंत साहू ने वार्ड 51 का दंगल जीता: लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 51 से कांग्रेस ने रेणु जयंत साहू को चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा ने यहां से उत्तर सिंह को चुनाव लड़ाया। कांग्रेस की रेनू जयंत साहू ने 183 मतों से जीत हासिल की। इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का ही कब्जा रहा और कामरान अंसारी यहां से पार्षद रहे।

वार्ड 65 से कांग्रेस के जयश्री नायक विजेती बनीं: महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 से जयश्री नायक कांग्रेस की उम्मीदवार थीं वहीं भाजपा ने मंजू यादव को उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर कांग्रेस की जयश्री नायक ने 584 मतों से जीत हासिल की। वहीं 2019 में इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा ओर सरिता वर्मा बीजेपी से पार्षद चुनी गई थीं।

10 सीटें कमल से रही दूर: नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में कमल खिला। सभी दस नगर निगमों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। पर कुछ सीटें ऐसी रहीं जहां न तो मोदी का मौजिक चला नहीं बीजेपी का अटल विश्वास पत्र काम आया। कांग्रेस की सात और निर्दलीयों की तीन सीट को मिलकर कुल 10 सीटें बीजेपी की आंधी में भी सेफ रहीं।

दिल्ली के अलग अलग समीकरण

आदिति फडणीस

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जिसने पार्टी को दिल्ली में सत्ता में स्थापित किया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पदाधिकारी ने कहा, ''मजा आ गया'' (पार्टी 1998 में सत्ता खो चुकी थी)। लेकिन नए मुख्यमंत्री की राह आसान नहीं होने वाली है। वह उन नए शक्ति समीकरणों का जिक्र कर रहे थे जो इस फैसले से दिल्ली के प्रशासन के लिए सामने आएंगे। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के उप-राज्यपाल (एल.जी.) को कई तरह से अधिकार दिए गए हैं। 2023 में, एक अध्यादेश जिसे बाद में संसद ने पारित किया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। प्राधिकरण एल.जी. को अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग तथा अनुशासनात्मक मामलों की सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब है कि निर्वाचित सरकार नौकरशाहों की नियुक्ति,स्थानांतरण, पदस्थापना नहीं कर सकती। पिछले साल 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) में नगर प्रशासन के विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों को नामित करने का एल.जी. का अधिकार उनके कार्यालय से जुड़ा एक वैधानिक कर्तव्य है और वह सहायता और सलाह से बाध्य नहीं हैं। विशिष्ट मुद्दा एम.सी.डी. में विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों की नियुक्ति थी, जिस पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि ही केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हैं, बाकी सभी मामलों में एल.जी. (और केंद्र) मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-दिल्ली सरकार संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून के पत्र पर भरोसा करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। साथ ही पहले के फैसलों ने निर्वाचित शासन और नियुक्त प्रशासक के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। फिर कुछ सप्ताह बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने के लिए एल.जी. को अधिकार सौंपे जो दिल्ली सरकार पर लागू हो। 'आप' ने इसका विरोध करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम,1999 की धारा 45 डी के साथ निर्णय लेने का अधिकार है। 'आप' के नीचे भाजपा को राजधानी पर नियंत्रण रखना होगा और सख्ती से शासन करना होगा। लेकिन भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के शासन में क्या ये शक्तियां अभी भी जरूरी होंगी, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इससे भी अधिक प्रासंगिक यह है कि क्या उप-राज्यपाल हल्के हाथ से शासन करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि उन्हें मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। दिल्ली-केंद्र संबंधों में एक और राजनीतिक पहलू है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। गृह मंत्रालय वह प्राधिकरण है जो दिल्ली के प्रशासन के ज्यादातर पहलुओं की देख-रेख करता है। अगले कुछ हफ्तों में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है। बहुत कुछ भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच समीकरण पर निर्भर करेगा। हमें कभी भी एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करना चाहिए,कई मायनों में, दिल्ली भाजपा मूल राज्य के संघर्ष से पीछे हट गई है। एक पार्टी अध्यक्ष इसे समझेगा और इससे सहानुभूति रखेगा। लेकिन क्या वह गृह मंत्रालय और एल.जी. को यह बताने के लिए राजनीतिक कद और अधिकार वाला व्यक्ति होगा कि एक निर्वाचित दिल्ली सरकार अब शहर के हितों में निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है? एम.सी.डी. पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। केंद्र के पास 2 विकल्प हैं, वह एम.सी.डी. को भंग करके नए चुनाव करा सकता है या फिर आयुक्त के माध्यम से निकाय चला सकता है। इससे शक्तियां और अधिक केंद्रीकृत हो जाती हैं और आपको आश्चर्य होता है कि एम.सी.डी. के चुनाव आखिर क्यों होते हैं।भाजपा और कांग्रेस को भी इस बात का अहसास है कि जमीन पर 'आप' अभी भी मौजूद है। दिल्ली विधानसभा की 14 सीटों पर कांग्रेस को 'आप' की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। कम से कम एक सीट पर, मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लिमीन (एम.आई.एम.) ने विपक्ष के तीन-तरफा विभाजन में योगदान दिया, जिसके कारण भाजपा (मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट) की जीत हुई। माना कि ये राजनीतिक समीकरण नहीं बल्कि अंक गणितीय हैं। लेकिन 'आप' को, जो वैसे भी सत्ताधारी पार्टी की तुलना में विपक्ष की भूमिका में ज्यादा सहज है, केंद्र के सामने उसकी शक्तिहीनता के बारे में भाजपा से असहज सवाल पूछने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।

कांग्रेस का एक और तुष्टीकरण का निर्णय

रमेश शर्मा

मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुये कांग्रेस ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। कॉंग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाली तैलंगाना सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे से मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी है । तैलंगाना से जनसंख्या के आंकड़ों में भी हेरफेर करने के आरोप सामने आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछली सरकार के सर्वे में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 51 प्रतिशत थी। लेकिन वर्तमान सरकार में यह आँकड़ा घटकर 46 रह गया। इससे यह चर्चा उठ खड़ी हुई है कि ओबीसी कोटे से मुसलमानों आरक्षण देने के लिये ही आँकड़ों में यह हेर फेर की जा रही है। यह आरोप किसी और ने नहीं अपितु केन्द्रीय मंत्री श्री बंटी संजय ने लगाया है। यदि केन्द्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है तो इसमें कुछ तथ्य अवश्य होगा। यह माना जा रहा है कि ओबीसी कोटे के मुस्लिम समाज को आरक्षण देने केलिये ही आँकड़ों में यह फेर की गई है।

ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का यह निर्णय पहला नहीं है इससे पहले भी कॉंग्रेस और उनके सहयोगी गठबंधन की सरकारों ने ओबीसी कोटे के अंतर्गत अपने अपने प्रदेशों में मुसलमानों को आरक्षण दिया है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल जैसे राज्य हैं। कर्नाटक में 32 प्रतिशत ओबीसी कोटा है इसमें भी मुस्लिम समाज को चार प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय हो गया है। कर्नाटक में कॉंग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान ने पहले भी ऐसा निर्णय लिया था । लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार आ गई थी, उस सरकार ने मुस्लिम समाज को ओबीसी में शामिल करने का निर्णय को ओबीसी हितों के विपरीत माना और रद्द कर दिया था।

कर्नाटक में जब पुन: कॉंग्रेस सरकार आई तो ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का आदेश पुन: लागू हो गया। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को दिया जाने वाला यह आरक्षण 3.5 प्रतिशत है। वहीं केरल में ओबीसी कोटे के अंतर्गत मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण बारह प्रतिशत है । यह किसी भी प्रॉंत में मुसलमानों को दिये जाने वाला आरक्षण सबसे अधिक प्रतिशत है। केरल में वामपंथी सरकार को मुस्लिम लीग का भी समर्थन है । यह वही मुस्लिम लीग है जिसने धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन कराया था और अगस्त 1946 में अपने डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत पूरे देश में हिन्दुओं पर हमले किये थे। विशेषकर बंगाल और पंजाब में लाखों हिन्दुओं की हत्या की गई थीं। कॉंग्रेस नेता श्री राहुल गाँधी ने अमेरिका यात्रा में इसी मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया था। जिस मुस्लिम लीग का इतिहास कट्टरपंथ और घोर साम्प्रदायिकता से भरा है उसे सेकुलर बताना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा मानी जा रही है।

मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत कॉंग्रेस इन दिनों दो बातों पर जोर दे रही है। एक आरक्षण का कोटा बढ़ाने केलिये और दूसरा जातीय आधारित जनगणना कराने पर । कॉंग्रेस द्वारा आरक्षण का कोटा बढ़ाने के पीछे भी मुसलमानों को आरक्षण देना है और जातीय आधारित जनगणना का उद्देश्य भी यही है। चूँकि कॉंग्रेस ओबीसी कोटे में मुसलमानों को शामिल करना चाहती है ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का प्रतिशत सामने आ सके और उस कोटे के अंतर्गत मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सके। चूँकि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। इसलिए धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान में आरक्षण का अधिकार अनुसूचित जाति, जनजाति को ही है। इस वर्ग में हिंदू, सिख और बौद्ध तो हैं पर मुसलमान नहीं आते। मुसलमानों को जनजाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता इसलिये ओबीसी को भी आरक्षण की माँग उठ रही है ताकि इस वर्ग समूह में मुसलमानों को शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कांग्रेस ने इसका रास्ता भी निकाल लिया है। कॉंग्रेस जिन दिनों सत्ता में थी तब दो आयोग बनाये गये थे। एक सच्चर कमेटी और दूसरी रंगनाथ मिश्रा कमेटी। इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट कॉंग्रेस की इच्छा के अनुरूप आई । इनमें मुस्लिम समुदाय पिछड़ा माना गया है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने तो धार्मिक आधार पर भी अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण देने की अनुसंशा कर दी है।

इस अनुशंसा में मुसलमानों 10 प्रतिशत और अन्य अल्पसंख्यकों को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। इसी के बाद से कॉंग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने और कोटा बढ़ाने की मांग आरंभ कर दी । कॉंग्रेस केवल माँग करने तक ही नहीं रुकी अपितु जिन राज्यों में उसकी और सहयोगी गठबंधन दलों की सरकारें हैं उन्होंने इस दिशा में काम करना भी आरंभ कर दिया है । इसी की झलक तैलंगाना, केरल, कर्नाटक और बंगाल जैसे प्रॉंतों में देखी जा सकती है।

कॉंग्रेस की यह तुष्टीकरण शैली केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत के बाहर अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी इस धारा पर काम कर रही है । इसे समझने केलिये फिलिस्तीन में आतंकवादी समूहों पर इस्राइल की कार्यवाही का विरोध करने से समझा जा सकता है । कॉंग्रेस फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर सामने आई, सड़क से संसद तक आवाज उठाई गई। लेकिन पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई जैसी फिलिस्तीन के समर्थन में आई। कॉंग्रेस नेता श्रीमती प्रियंका गांधी तो फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर संसद में भी पहुँच गईं थीं।

कॉंग्रेस नेता श्री राहुल गाँधी संविधान के प्रतीक के रूप में एक लाल किताब लेकर चलते हैं । संविधान को सर्वोच्च बताने की बात भी हर सभा में करते हैं लेकिन संभल में वे उन लोगों के समर्थन में सामने आये जिन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वे का विरोध किया था और हिंसा की थी । चूँकि वे सभी मुस्लिम समाज के थे, क्या इसीलिए श्री राहुल गाँधी ने उन्हें पीड़ित बताया और उनके परिवारों से मिलने भी गये।

ऐसा नहीं है कि सत्ता से बाहर होने के बाद कॉंग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कॉंग्रेस की प्राथमिकता में सदैव मुसलमान ही रहे हैं। कॉंग्रेस ने अपनी यह प्राथमिकता कभी छुपाई भी नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में कॉंग्रेस नेता श्री मनमोहन सिंह ने खुलकर कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह बात प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने तो कही ही थी । उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी या उनके बाद श्री नरसिंहराव आदि सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में लिये गये निर्णयों में भी कॉंग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति स्पष्ट है। मुस्लिम पर्सनल लॉं के अंतर्गत धार्मिक विशेषाधिकार, वक्फ बोर्ड को विशिष्ट अधिकार देने जैसे निर्णय शामिल हैं। यही नहीं यदि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश आया तो मुस्लिम तुष्टीकरण केलिये संसद द्वारा संविधान संशोधन कर दिया गया । इसे शाहबानू को न्यायालय द्वारा गुजारा भत्ता देने के आदेश से समझ सकते हैं। एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का यह आदेश संसद द्वारा बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त नरसिंहराव सरकार में धार्मिक स्थलों की स्थिति को 1947 के स्वरूप को यथा स्थिति बनाये रखने के संशोधन भी मुस्लिम तुष्टीकरण का एक बड़ा उदाहरण है।

मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और निर्णयों से कॉंग्रेस का इतिहास भरा है । कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनसे भारतीय समाज जीवन को स्थाई दर्द मिला है। ऐसा एक निर्णय वर्ष 1921 का है। कॉंग्रेस ने तब स्वतंत्रता के लिये आरंभ हुये असहयोग आँदोलन में खिलाफत आँदोलन को जोड़ने की घोषणा की थी और ये दोनों आँदोलन साथ साथ चलाये थे। असहयोग आँदोलन तो भारत की स्वतंत्रता केलिये था लेकिन खिलाफत आँदोलन मुसलमानों की धार्मिक सत्ता के प्रमुख खलीफा को बहाल करने केलिये था। खलीफा का भारत से कोई संबंध नहीं था। बल्कि मध्काल में खलीफा के आदेश पर भारत पर हुये हमलों, लूट और कत्लेआम का एक लंबा इतिहास है। उन दिनों खलीफा का केन्द्र तुर्की था । खलीफा के समर्थन में दुनियाँ के किसी मुस्लिम देश ने कोई आँदोलन नहीं चलाया। लेकिन कॉंग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण केलिये भारतीय जन मानस को खलीफा के समर्थन में सड़क पर उतार दिया था। इसमें खलीफा की बहाली तो न हो सकी लेकिन मुस्लिम लीग को पूरे भारत के मुसलमानों में कट्टरपंथ फैलाने और उन्हें एकजुट करने का रास्ता मिल गया था। यही कट्टरता आगे चलकर भारत विभाजन और लाखों हिन्दुओं की हत्या का कारण बनी। इसी वर्ष भारत में दो घटनाएँ और घटीं थीं। एक घटना मालाबार में घटी। वहाँ कट्टरपंथियों द्वारा हिन्दुओं से पूरा मालाबार खाली कराने केलिये किये गये सामूहिक नरसंहार, स्त्रियों के अपहरण से पूरा क्षेत्र काँप गया था। गांव के गाँव उजाड़ दिये गये थे। कयी दिनों लाशें पड़ी सड़ती रहीं थीं। खेतों और घरों पर कब्जे कर लिये गये थे। लेकिन कॉंग्रेस ने एक शब्द न कहा, चुप्पी साधे रही। लेकिन इसी बीच असहयोग आँदोलन के दौरान चौरी चौरा में हिंसा हुई तो आँदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा हिंसा केलिये अधिकांश हिन्दुओं को आरोपी बनाया गया था। इसमें कुछ तो गोरख पीठ के संत थे । लेकिन कॉंग्रेस ने आँदोलन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने पूरे क्षेत्र में कैसा दमन चक्र चलाया यह भी इतिहास के पन्नों में उपलब्ध हैं। कॉंग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का एक और बड़ा उदाहरण अंग्रेजी काल में लोकल असेम्बली चुनाव की नियमावली तैयार करने में अंग्रेज सरकार के निर्णय पर सहमति जताने में दिखता है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभु:। वृषस्य नष्टांस्त्रीन्पादांस्तप: शौचं दयामिति।। प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्द्धयत्। (श्रीमद्भागवत 1 । 16-16 अध्याय)

अर्थात् (ख) (दिग्विजय से लौटते हुये राजा परीक्षित ने सरस्वती के किनारे देखा) एक गाय और बैल का जोड़ा खड़ा है तथा राजा के समान मुकुट आदि धारण किये एक वृषल (धर्म विध्वंसक शूद्र) हाथ में दण्ड उठा कर उसे अनाथ की तरह पीट रहा है। वह बैल कमलनाल बिस के समान धवल है और डर से सूत्र छोड़ रहा है, तथा केवल एक पांव के सहारे दु:खित दशा में खड़ा हुआ शूद्र से पीटा गया कांप रहा है। वह धर्मदुघा गाय भी शूद्र द्वारा बार बार पांव की ठोकरों से ठुकराई हुई अत्यन्त दीन हो रही है। आंख से आंसू टपक रहे हैं, मानो इसका वत्स नष्ट हो गया। वह दुखित एवं थकित होकर घास को चाह रही है। सुवर्णजटित रथ में बैठे हुये राजा ने पूछा कि मेरी रक्षा में रहने वाली प्रजा को बलात् मारने वाला तू कौन बली है ? तथा ऐ चारपाए बैल! तेरे यह तीन पांव किसने काट डाले? (धर्मरूप बैल के सब कुछ बताने पर) राजा ने भूमिरूप गाय और धर्मरूप बैल को आश्वासन दिया, तथा उस कलिकालरूपी राजवेश-धारी शूद्र को मारने के लिये तीखी तलवार उठाई। जब शूद्र ने देखा कि राजा मुझे मार ही डालेगा, तो वह राजवेश त्याग कर भयाकुल हो चरणों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित उसे पांव में पड़े देखकर करुणाविष्ट हो गये और उसे शरणागत जान वार न किया, तथा हंसने लगे कि ऐ पापिष्ठ! खबरदार ! मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जा। परीक्षित की ऐसी आज्ञा पाकर खड्ग उठाये साक्षात् काल के समान सिर पर खड़े राजा के प्रति कांपते हुए कलि ने कहा कि- हे धर्मात्मन्!

क्रमश: ...

गोपाल कृष्ण गोखले

धीरज पाल

आज महान स्वतंत्रतासेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि है। गोखले मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये वही नेता हैं जिसने सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बताए जा रहे विधेयक के विरोध में लेजिस्टलेटिव बार काउंसिल से वॉक आउट कर दिया था। इनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण की वजह से महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों ही इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी और जिन्ना गोपालकृष्ण गोखले को क्यों अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, इसे जानने के लिए, सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ बाते जान लेनी चाहिए।

गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ई में जिला रत्नागिरी, तालुका गुहागर के कोथलुक नामक गांव में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि गोखले अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और ब्रिटिश राज में कोई छोटी-मोटी नौकरी कर सकें। इन कठिनाईयों के बीच गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना ग्रैजुएशन एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरा किया। इनके पिता का नाम कृष्णा राव गोखले और माता वालुबाई गोखले था।

गोखले सन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। वे हमेशा जनता की परेशानियों के लिए कार्यरत रहे। कुछ समय के बाद बाल गंगाधर तिलक के साथ गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। हालांकि दोनों में काफी मतभेद थे जिसकी वजह से सन् 1905 में गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस को भागों में बट गई। जहां तिलक ब्रिटिश सरकार को क्रांति कर आजादी लेना चाहते थे तो वहीं गोखले शांतिपूर्ण वार्ता और समन्वयवादी नेता थे।

कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गोखले ने सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके पीछे गोखले का मकसद था कि भारतीयों को जागरुक और शिक्षित करना। इस सोसाइटी ने कई स्कूल, कॉलेज की स्थापना की गई।

सन् 1912 में गांधीजी के आमंत्रण पर गोखले ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। यात्रा के बाद गांधी और गोखले ने एक साथ कई महीने साथ बिताएं। उस दौरान गांधी जी नए-नए बैरिस्टर बने थे और साउथ अफ्रीका में अपने आंदोलन के बाद भारत लौटे थे। इसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में किया था। उन्होंने भारत के बारे में और भारतीय विचारों को करीब से जानने व समझने के लिए गोखले का साथ चुना और उनके परामर्श के अनुसार कार्य किए।

ऐसा नहीं था कि गोखले सिर्फ गांधी को प्रिय थे या अपना उन्हें राजनैतिक गुरु मानते थे। उस समय के एक और नेता मोहम्मद अली जिन्ना गोखले से इतने प्रभावित थे। जिन्ना ने एक तकरीर के दौरान कहा था कि अगर मैं मुसलमान गोखले बन सका तो मेरा जीवन सफल होगा। कुछ इस तरह थे गोपालकृष्ण गोखले।

गोखले अपना सारा जीवन भारत को को आजाद और राजनैतिक सक्रियता में दे दिया। उनकी मृत्यु सन 19 फरवरी सन् 1915 को हुई। उस वक्त उनकी उम्र महज 49 वर्ष की थी।

भारत के इस दोस्त से इतना क्यों डरते हैं ट्रंप?

अभिनय आकाश

प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑन द लाइन। कैन यू प्लीज कनेक्ट टू द प्रेसिडेंट पुतिन। ये सुनते ही मॉस्को के एक कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पिछले तीन बरसों से इस कॉल का इंतजार था। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से अमेरिका से उनकी बातचीत बंद थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 फरवरी के रात दो लोगों को फोन लगाया। पहला फोन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और दोनों के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई इसके बाद ट्रंप बोले की पुतिन जंग रोकने के लिए बातचीत को तैयार हैं और हम मिलकर इसपर काम करेंगे। ट्रम्प का अगला फोन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की को गया। दोनों के बीच करीब 60 मिनट तक बातचीत हुई इसके बाद ट्रंप ने बताया कि पुतिन की तरह ही जेलेन्स्की भी जंग रोकने के लिए तैयार है। दोनों फोन कॉल के बाद ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

ट्रंप ने कहा कि मैं और पत्नी जल्दी सऊदी अरब में मिलने वाले लेकिन जब ट्रम्प से पूछा गया कि क्या यूक्रेन भी जाएंगे तो कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन को नाटो के सदस्यता मिलना प्रैक्टिकल नहीं है। ट्रंप के इन बयानों को कुछ जानकार पुतिन की कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल के दौरान अमेरिका कभी भी रूस की तरफ मध्यस्थता का हाथ बढ़ाते नहीं दिखा। इन तीन सालों में अधिकतर जो बाइडेन राष्ट्रपति रहे। मार्च 2023 में बाइडेन ने पुतिन को मर्डर डिक्टेटर तक कह दिया था। बड़े ने सारे कूटनीतिक संबंध भी खत्म कर दिए थे। यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ही दे रहा था। उसने रूस पर लंबे चौड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। दूसरी ओर यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलता रहा। ऐसे में पुतिन के अमेरिका जाने का तो सवाल उठता ही नहीं था। लेकिन जनवरी 2025 में कहानी पलट गई और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया। बाइडेन के अप्रोच के ठीक उलट ट्रंप नई चुनावी कैंपेन में यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद की आलोचना की थी। अब जब वह राष्ट्रपति है तो खुलकर बनी बनाई व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं।

ये तो साफ है कि रूस 2014 वाली स्थिति से पीछे नहीं जाएगा। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। 2022 की जंग में उसने यूक्रेन के चार नए प्रांतों डोनेट्स्क, खेरसॉन, लुहान्स्क और जापोरिजिया को अपना हिस्सा बनाया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन्हें मान्यता नहीं दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस कब्जाए इलाकों को वापस करे। जेलेंस्की ने द गार्जियन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस के कुर्स्क क्षेत्र को वापस देने की पेशकश करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे बदले में कौन से क्षेत्र मांगेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुछ तय नहीं है। हमारे लिए सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। हम एक इलाके के बदले दूसरा इलाका देंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन ने छह महीने पहले रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। रूस लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन को वहां से हटा नहीं पाया है।

रूस अब तक 20% यूक्रेन के हिस्सों को कब्जा चुका। क्रीमिया पर 2014 में कब्जा। डोनेस्क, खार्किव, खेरसॉन, लुहान्सक और जापोरिज्या ओब्लास्ट पर भी कब्जा कर चुका है।12,456 लोगों की जंग में मौत। वहीं, 28,382 लोग घायल हुए। यूक्रेन के अनुसार रूस के 4,30790 सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि, रूस ने इससे इनकार किया है। स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार जंग में एक लाख सैनिकों की मौत हुई है। इसमें यूक्रेन के 40 हजार सैनिक भी शामिल हैं। यूक्रेन चाहता है कि कब्जा की गई जमीन उसे वापस मिले और 2014 वाली बॉन्ड्री रिस्टोर कर दी जाए। यूक्रेन इन सब के अलावा नाटो की सदस्यता भी चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप जंग रुकवाते हुए ये सब सुनिश्चित कर पाएंगे। क्या वो यूक्रेन को 2014 वाली बॉन्ड्री वापस दिला पाएंगे।

एक चीज आपको साफ नजर आएगी कि ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन करे से सुना और जेलेंस्की को अपनी बात सुनाई। अमेरिका की ट्रंप सरकार पुतिन के समर्थन में ज्यादा दिखती है। यूक्रेन वॉर का पीस प्लान रूस और अमेरिका मिलकर तय करेंगे। यूक्रेन इसमें थर्ड पार्टी की तरह होगा। यूक्रेन एक प्लेयर है लेकिन वो अब खेल को प्रभावित करने की स्थिति में अब नहीं रहा। जो इलाके रूस ने कब्जाएं हैं उनमें से ज्यादातर या एक बड़ा हिस्सा रूस के पास रह सकता है। कम से कम एक रूस और अमेरिका का प्लान तो ऐसा ही लगता है। यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। बेल्जियम में नाटो मुख्यालय में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। उन्होंने यह डी कहा कि यथार्थवादी शांति योजना के तहत ट्रम्प यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। हेगसेथ ने कहा कि यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना अब असंभव है। ट्रंप ने भी कहा है कि वो यूक्रेन के नाटो मेंबरशिप का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको याद होगा जुलाई 2024 में नाटो की 75वीं सालगिरह के मौके पर जेलेंस्की की मौजूदगी थी। तब कहा गया था कि यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप अकाट्य है और इसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इससे ठीक उलट ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके पीस प्लान में ऐसा कुछ नहीं है और रूस के बुनियादी शर्तों में से ही है।

युद्ध को लेकर प्रस्तावित समझौते में यूक्रेन का जिक्र नहीं होने से पूरे यूरोप में हलचल है। यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहीं अपनी शर्तों पर यह समझौता न कर लें। उनका मानना है कि ट्रम्प प्रशासन रूस को बड़ी रियायतें दे सकता है, जिससे यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसमें यूक्रेन व पूरे यूरोप को धक्का लगेगा। इस बीच यूरोपीय देशों ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना शांति वार्ता मंजूर नहीं है।

आज का इतिहास

1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई शहर डार्विन पर जापानी लड़ाकू विमानों के हमले में 243 लोग मारे गए।

1943 खारकोव की तीसरी लड़ाई शुरू हुई।

1959 साइप्रस की स्वतंत्रता के बारे में यूनान, तुर्की और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ।

1963 बेट्टी फ्रेडन की द फेमिनिन मिस्टिक, एक गैर-काल्पनिक किताब है, जिसे द अनटाइटेड स्टेट्स में सेकंड-वेव फेमिनिज्म की शुरुआत में स्पार्किंग के साथ प्रकाशित किया गया था।

1965 वियतनाम गणराज्य की सेना के कर्नल फाम नोक थोओ और उत्तर वियतनामी वियतनाम के एक कम्युनिस्ट जासूस के साथ, जेनराल्स लैम वान फाट और ट्रान थिएन खीम ने गुयेन खान के विषयगत जुंटा के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया।

1966 यूनाइटेड किंगडम के नौसैनिक मंत्री क्रिस्टोफर मेयू ने इस्तीफा दिया।

1986 सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था, जिसने अंतरिक्ष में पहला दीर्घकालिक अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया।

1992 केन लुडविग के संगीतमय क्रेजी फॉर यू का प्रीमियर 19 फरवरी, 1992 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। इसे 1622 के प्रदर्शन के लिए शटबर्ट थियेटर न्यूयॉर्क में उसी तिथि को खोला गया था।

1993 केन्या मूर, एक 22 वर्षीय लड़की माइक्रिगन को 19 फरवरी, 1993 को 42 वें मिस यूएसए के रूप में ताज पहनाया गया था।

1993 हैतो के पास समुद्र में 1500 यात्रियों सहित एक जहाज डूबा।

1997 चीन के वरिष्ठ नेता और देश में आर्थिक सुधार की नींव डालने वाले डेंग ज़ियाओ पेंग का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

1999 डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई।

2003 ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की सैन्य उड़ान सिराक पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपदा में 275 लोग मारे गए थे।

2006 मेक्सिको के न्यूवा रोसेटा में एक कोयला खदान में एक मिथेन विस्फोट, 65 खनिक फंस गया और मारे गए।

दिल्ली विस चुनाव : यह राजनीति में नैतिक उम्मीद की भी हार है..!

अजय बोकिल

यूं दिल्ली विधानसभा और सरकार की हैसियत किसी बड़े नगर निगम से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी हार-जीत का संदेश देश की राजनीति की दिशा और दशा जरूर तय करता है। इस बार दिल्ली राज्य विधानसभा के चुनाव में डेढ़ दशक से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की करारी हार सत्ता स्वार्थ के आगे नैतिकता को आवारा छोड़ने की धूर्तता, कथनी और करनी में लगातार गहराते अंतर और भ्रष्टाचार के खिलाफ चले अण्णा आंदोलन के बाद उभरी वैकल्पिक राजनीति में नैतिक उम्मीद की भी करारी हार है।

बेशक इस कांटे की लड़ाई में देश पर राज कर रही बीजेपी ने तीन दशक बाद अपनी जबर्दस्त चुनावी रणनीति से दिल्ली राज्य का किला सर कर लिया है, तो इसके पीछे बड़ी वजह देश की राजधानी के मतदाता का आम आदमी पार्टी से हुआ मोहभंग बड़ा कारण है। इस चुनाव नतीजे के तीन सबक हैं।

पहला तो यह कि कोई भी राजनीति पार्टी भले ही कितनी नीतिमत्ता के दावे करे, सत्ता की काजल की कोठरी के दाग से नहीं बच पाती। दूसरे, केवल रेवड़ी बांटना ही अब चुनावी जीत का प्रमुख कारण नहीं रह गया है। वरना इस रेवड़ी कल्चर के पोस्टर ब्वॉय खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं गंवाते। तीसरा, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, यह दूसरे राजनीतिक दलों को भाजपा से सीखना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की राजधानी में तीन बार भगवा फहराने के बाद भी लाल किले की प्राचीर आम आदमी पार्टी के अभेद्य बनी हुई थी। शुरू में केजरीवाल की अलग सियासी लाइन दिल्ली के मतदाताओं को मोहित किया था। कांग्रेस, बीजेपी और साम्यवादियों की वैचारिक राजनीतिक लाइन से हटकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पर काबिज रहने की एक ऐसी गड्डमड्ड संस्कृति विकसित कर ली थी, जिसमें मतदाता को मुफ्तखोरी का लती बनाना, खुद अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटना, वक्त पड़ने पर मुकर जाना, खुद को धार्मिक व्यक्ति तथा गरीब हितैषी के रूप में पेश करना शामिल था।

सबसे बड़ी विडंबना ये कि भ्रष्टाचार जैसी जिस गंभीर सामाजिक राजनीतिक बुराई के खिलाफ लड़ने के संकल्प के साथ आप दिल्ली में सत्ता में आई थी, वो खुद शराब घोटाले के रूप में उसी में डुबकी लगाने लगी, बावजूद इसके कि व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल और उनकी मंडली का इस घोटाले में लिप्त होना अभी अदालत में साबित होना है। लेकिन भ्रष्टाचार का दाग वास्तविक भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा गहरा होता है, जो आसानी से नहीं छूटता। 'कट्टर ईमानदार' जैसा अनोखा मुहावरा हिंदी को अरविंद केजरीवाल ने ही दिया था, लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने उन्हें कट्टर बेईमान के आईने में देखा।

इस चुनाव में आप की करारी हार के लिए भाजपा के आक्रामक प्रचार से अधिक आप की गलतियां ज्यादा जिम्मेदार है। इसकी एक बड़ी वजह केजरीवाल का

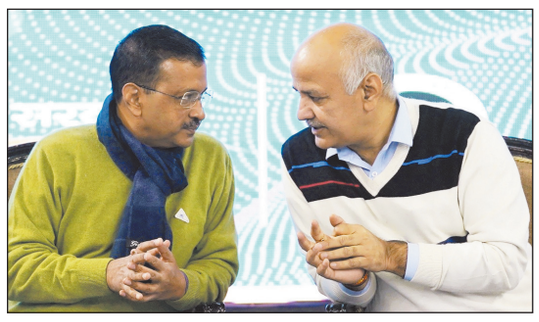

अहंभावी होना है। उनकी हार की सबसे ज्यादा खुशी उनके पूर्व साथियों और आप के हाथों दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन गंवाने वाली कांग्रेस को है, जो चुनाव में एक भी सीट न जीतने के बावजूद इस बात से गदगद है कि केजरीवाल हारे और कांग्रेस का वोट 2 फीसदी बढ़ा।

उधर आप अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में किए गए कुछ कामों और साथ में बांटी जा रही रेवड़ियों को सत्ता का आजीवन पट्टा मानकर चल रही थी। जिसे दिल्ली के मतदाता ने ही निरस्त कर दिया है। केजरीवाल की गारंटियों और वैकल्पिक राजनीति के वादों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और दिल्ली के समुचित विकास के वादे भारी पड़े हैं। इस नतीजे में यह संदेश भी निहित है कि कोई राज्य सरकार हर मुद्दे पर केन्द्र सरकार से टकराव लेकर सत्ता में बने रहना चाहेगी तो यह लंबे समय तक मुमकिन नहीं है, बावजूद इसके कि बीजेपी ने भी केजरीवाल के हाथो मे बेड़ियां डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थीं।

आप की इस हार का बड़ा कारण दिल्ली में मध्य वर्ग का पार्टी से मोहभंग है। ये मध्यवर्ग मुख्य रूप से वेतन भोगी है। मोदी सरकार द्वारा इस बाद बजट में इनकम टैक्स में छूट सीमा बढ़ाने और आठवें वेतन आयोग के गठन ने मध्य वर्ग को वापस भाजपा की तरफ मोड़ दिया। इसी तरह निम्न वर्ग और महिलाओं ने भी आप के बजाए बीजेपी को ज्यादा वोट किया।

सवाल यह कि आप की दिल्ली विस चुनाव में भारी हार का राजनीतिक संदेश क्या है? आप की पराजय ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर एक और घनाघात किया है। ऐसे में यह गठबंधन कितना चल पाएगा, कहना मुश्किल है। अगर विपक्ष एक नहीं हो पाता है और राज्यों के चुनावों में वो हो भी नहीं रहा है, यह सत्तारूढ़ भाजपा के लिए सुखद खबर है। दिल्ली की हार का सीधा और पहला असर पंजाब की राजनीति पर होगा। वहां आप की सरकार है। संभव है कि कांग्रेस छोड़कर आप में गए कई नेता अपनी मूल पार्टी में लौटने लगें, क्योंकि अब केजरीवाल जीत की गारंटी नहीं रह गए हैं।

आप की हार क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक आकांक्षाओं पर भी बड़ा वज्रपात है। क्योंकि भाजपा दिल्ली में ही नहीं जीती है, उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित मिलकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी उसने जीत लिया है, जो समाजवादी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि संविधान बचाने, जाति जनगणना और ईवीएम में गड़बड़ी जैसे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में चल गए थे, अब संजीवनी शक्ति खो चुके हैं।

विपक्ष को भाजपा से मुकाबले के लिए नए और असरदार मुद्दों की तलाश करनी होगी। क्योंकि भाजपा की जीत के मूल में उसकी सुस्पष्ट रणनीति, मुद्दों की पकड़, प्रभावी बूथ मैनेजमेंट और संकल्पशक्ति है।

दिलचस्प बात यह है कि अरविंद का अर्थ भी कमल होता है और भाजपा का चुनाव चिन्ह भी कमल ही है। यानी दिल्ली में फिर कमल ने ही कमल को हरा दिया है। फर्क इतना है कि भाजपा आप को 'आपदा' साबित करने में कामयाब हो गई जबकि आप को बेनकाब नहीं कर पाई।

दिल्ली विजय के साथ भाजपा का उत्तर भारत में राजनीतिक अश्वमेध काफी हद तक पूरा हो चुका है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो उसे अभी भी अपनी सियासी जमीन और उन मुद्दों की तलाश है जो उसे खोया हुआ राजनीतिक वैभव लौटा सके। लोकसभा चुनाव की पिच पर मिली सफलता का सिलसिला पार्टी राज्यों के विकेट पर जारी नहीं रख पाई है।

प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उसे क्या और कैसी भूमिका निभानी है, इसको लेकर भ्रम कायम है। क्योंकि दिल्ली में चुनाव के चलते महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उछालना राजनीतिक विवेक का परिचायक कतई नहीं कहा जा सकता।

प्रगति यात्रा के सहारे चुनावी नैया पार उतारने की कोशिश में नीतीश

उमेश चतुर्वेदी

बिहार में विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। छह महीने बाद राज्य में चुनाव होने हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष-दोनों ने चुनावी समर के लिए कमर कस लिया है। इन तैयारियों के बीच एक बात तय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार की ही अगुआई में चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। पिछले साल नीतीश और लालू के मिलने की खबरिया कानाफूसी हो रही थी, उन्हीं दिनों पहले अमित शाह और बाद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दोनों नीतीश के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। वहीं विपक्षी खेमे की कमान बीमारी के बावजूद लालू यादव ने अपने हाथ में ले ली है।

जनता दल से अलग होकर जब से नीतीश कुमार ने अपनी अलग राह चुनी है, बिहार में ज्यादातर जंग लालू बनाम नीतीश ही रही है। सियासी इतिहास गवाह है कि जब भी लालू बनाम नीतीश की जंग होती है, लालू का जंगलराज के भूत का डर बिहार के लोगों को सताने लगता है। इस जंग में लालू की बनिस्बत नीतीश का चमकदार और सुलझा हुआ सामने आ जाता है और सियासी बाजी नीतीश की अगुआई वाले गठबंधन के ही हाथ लगती रही है। एनडीए अगर बिहार की सत्ता से अतीत में कभी दूर हुआ भी है तो उसकी वजह खुद नीतीश का उसका साथ छोड़ना रहा है।

नीतीश कुमार की अगुआई में 2005 में बिहार की सत्ता पर एनडीए के काबिज होने के बाद बिहार की अराजक छवि में तेजी से बदलाव हुआ। शासन की गाड़ी पटरी पर लगातार आती गई। नीतीश के पहले बिहार में बिजली के दर्शन कभी-कभी होते थे, लेकिन बाद में हालात बदले। बिहार की सड़कें देश और दुनिया में अपनी बदहाली के लिए जानी जाती थीं, लेकिन नीतीश ने उन्हें भी बदला। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिलों की सौगात मिली। कभी माफिया, अपहरण और वसूली के लिए बदनाम बिहार की छवि बदलने लगी। इसके बाद नीतीश कुमार की भी नई छवि बनी, उन्हें नया नाम भी मिला, सुशासन कुमार। पंद्रह साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में नीतीश की पार्टी की सीटें घटीं। हाल के दिनों में उनके कुछ बयानों पर सवाल भी उठे, इसके बावजूद बिहार की राजनीति का सबसे चमकदार चेहरा अब भी नीतीश कुमार ही हैं। शायद यही वजह है कि एनडीए एक बार नीतीश कुमार के ही चेहरे के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। एनडीए और जनता दल यू को लगता है कि इस जंग में इस बार सियासी कामयाबी दिलाने में मददगार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ही हो सकती है। इसलिए सत्ताधारी खेमे की ओर से एक तरफ जहां विकास को मुद्दा बनाने की तैयारी है, वहीं विकास के सिलसिले में नए आयाम जोड़ने को लेकर तेजी से काम हो रहा है। इसी के तहत नीतीश सरकार सड़क और पुल निर्माण जैसे विकास कार्यों को ज़मीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है।

एनडीए के साथ ही बिहार के सियासी जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। क्योंकि नीतीश सरकार की नीतियों की वजह से पहले से ही समूचे राज्य में बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही लोगों की राय जानने के लिए कुछ दिनों पहले से नीतीश कुमार ने राज्य में प्रगति यात्रा की। इस यात्रा के दौरान नीतीश ने राज्य के तमाम जिलों में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सुनवाई की जगह पर ही अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। विशेष रूप से सड़क निर्माण, बाईपास और उच्चस्तरीय रेलवे ओवर ब्रिज की योजनाओं पर जोर दिया गया, ताकि राज्य में आवागमन की सुगमता बढ़े और यात्रा समय में कमी आए।

प्रगति यात्रा के ही दौरान नीतीश कुमार ने 20,000 करोड़ रुपये की 188 योजनाओं की घोषणा की, जिनमें 121 योजनाओं को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है और उन्हें जमीनी हकीकत बनाने को लेकर तेजी से काम शुरू हो चुका है। इनमें से कई योजनाएं ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने, उनका पुनर्निर्माण करने और उनकी हालत पहले की तुलना में और बेहतर बनाने को लेकर हैं। इस दौरान समस्तीपुर और मधेपुरा जिलों में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही, सीवान, छपरा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों में सड़क चौड़ीकरण, बाईपास और पुल निर्माण कार्यों के लिए भी भारी धनराशि स्वीकृत की गई है। सत्ताधारी खेमे का दावा है कि नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत की वजह से बिहार का तकरीबन हर गांव पक्की और चौड़ी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं। जिनकी मदद से बिहार के किसी भी कोने से पहले की तुलना में राजधानी पटना पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हुआ है। इसकी वजह से लोगों के समय और ईंधन की बचत हो रही है। नीतीश की अगुआई में 2010 में मिली दूसरी जीत में बेहतर सड़कों की बड़ी भूमिका रही। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के लिए खजाना खोल दिया है। नीतीश के लिए चुनौती शराबबंदी बनी हुई है। सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार की वजह से शराब की तस्करी बढ़ी है। हालांकि शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। नीतीश को इस चुनौती से पार पाना होगा। वैसे प्रशांत किशोर जैसे उनके पुराने साथी विपक्षी खेमे की ओर से इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। फिर भी कह सकते हैं कि बिहार की आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ा नीतीश सरकार का पहिया अब भी प्रमुख मुद्दा है। उम्मीद की जा रही है कि चुनावों की घोषणा होने तक नीतीश और बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित और विस्तारित करते रहेंगे।

मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ अदालत

नीरजा चौधरी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावों से पहले दी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों की जिस तरह आलोचना की है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत में दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे मिल रहे हैं। अदालत द्वारा यह टिप्पणी तब की गयी, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ तय करते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें उन लोगों के लिए पैसे खर्च कर रही हैं, जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब न्यायिक अधिकारियों के वेतन और उनकी पेंशन की बात आती है, तो वित्तीय संकट का बहाना किया जाता है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के जरिये सरकार से पूछा कि मुफ्त की योजनायें लागू करके आप परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे?

यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई की है। पिछले साल शीर्ष अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज या मुफ्त सुविधायें देने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। हाल के दौर में राजनीतिक दलों ने वोट हासिल करने के लिए मुफ्त की योजनाओं और आर्थिक लाभ देने पर बहुत अधिक भरोसा किया है। जबकि इनसे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। रिजर्व बैंक ने विगत दिसंबर में जारी अपनी रिपोर्ट में भी फ्रीबीज पर चिंता जताते हुए कहा है कि कई राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के अपने बजट में कृषि ऋण माफी, कृषि और घर को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगारी भत्ता और नकद

सहायता देने की घोषणायें की हैं। इस तरह के खर्चों से उनके पास अपने उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकता है।

लेकिन इस सबसे बेपरवाह हर राजनीतिक पार्टी चुनाव के समय मतदाताओं को मुफ्त सुविधा देने का वादा करती है। हाल के चुनावों में हमने राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त सुविधा देने के वादे करते देखा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं से मुफ्त सुविधाओं के वादे किये थे। चुनावों में प्रधानमंत्री की अपनी गारंटी की बात होती है। मतदाताओं को मुफ्त सुविधायें देने का असर यह हुआ है कि देश भर में महिलाओं का अलग वोट बैंक बन चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले घूमते हुए मैंने महिला मतदाताओं से जब उनकी राय पूछी थी, तब उनका कहना था कि हमारे पति अगर कांग्रेस को वोट देते हैं, तो भी हम एकनाथ शिंदे को वोट देंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे हित में वादे किये हैं।

मैं पर यहां दो बातें कहना चाहूंगी। एक यह कि फ्रीबीज पर अंकुश लगाने का काम आसान नहीं। तब तो और नहीं, जब अभी तक इसकी सर्वमान्य परिभाषा तय नहीं की गयी है। दूसरा, खासकर महिलाओं को जो आर्थिक लाभ दिये जा रहे हैं, वे बेहद उपयोगी साबित हुए हैं। महाराष्ट्र में अनेक महिलाओं ने मुझसे कहा कि सरकार उन्हें जो पैसे देती है, उससे उन्होंने छोटा-मोटा कारोबार शुरू किया है। कई दलित महिलाओं ने बताया कि सरकारी पैसे से उन्होंने सब्जियों का ठेला शुरू किया है। यानी मुफ्त लाभ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है।

दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होने का लाभ यह हुआ है कि घरों में काम करने वाली अनेक महिलायें लाल किला और इंडिया गेट घूमने जा पा रही हैं। ऐसा वह पहले नहीं कर पाती थीं। इससे फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि सरकारों का विकास मॉडल विफल वर्षों पहले विफल हो चुका है। समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं की आत्मनिर्भरता ही तो हमारे लोकतंत्र का लक्ष्य थी। चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को पैसे दिये जाने की शुरुआत हुई, तो इससे वे आत्मनिर्भर होने लगीं। लिहाजा इन पर अंकुश लगाने का जोखिम शायद ही राजनीतिक पार्टियां उठायें।

जब मुफ्त रेवड़ी क्या है, अभी इसकी परिभाषा ही तय नहीं है, तब इस पर अंकुश लगाया जाये भी, तो कैसे? जुलाई, 2022 में यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तब प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने इसे लेकर लंबी सुनवाई की थी। पर मामला संवैधानिक हो जाने और उनके रिटायर होने से यह मामला टलता रहा। वर्ष 2022 में ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि फ्रीबीज की कोई परिभाषा उसके पास नहीं है, इसलिए वह इस पर रोक लगाने में अक्षम है। तब आयोग ने शीर्ष अदालत से ही इसकी परिभाषा तय करने के लिए कहा था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने चुनाव आयोग के इस रुख पर नाराजगी जतायी थी। अक्तूबर, 2024 में इस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से इस पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। पर केंद्र ने अभी तक शपथपत्र दायर नहीं किया है।

राजनीतिक पार्टियों द्वारा सब कुछ मुफ्त देने के वादे करना बहुत आसान है, लेकिन उन पर अमल करना मुश्किल है। सभी पार्टियां वादा निभा पाती हों, ऐसा भी नहीं है। पंजाब में आप और कर्नाटक में कांग्रेस संसाधनों के अभाव में बहुत सारे चुनावे वादों पर अमल नहीं कर पायी हैं। दिल्ली में मतदाताओं ने भाजपा को इसलिए जिताया, क्योंकि उन्हें लग गया था कि केजरीवाल जीत भी गये, तो वादे पूरे नहीं कर पायेंगे। यानी मुफ्त सुविधाओं की राजनीति में वही भारी पड़ेगा, जिसके पास संसाधन ज्यादा हों। इस मामले में फिलहाल भाजपा दूसरी तमाम पार्टियों पर भारी पड़ती दिखायी देती है। यानी यहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो जरूर एक चिंताजनक बात है।

ऐसे में, चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाओं के वादे करने के मामले में कोई न कोई मानक तो तय करना होगा। चूंकि मुफ्त सुविधायें चुनाव से जुड़ी हैं, ऐसे में, इस पर दिशा-निर्देश तय करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन इस मुद्दे पर उसने कुछ किया नहीं। ऐसे में, राजनीतिक पार्टियों को सर्वसम्मति से इसका कोई हल निकालना चाहिए। पर अव्वल तो मुफ्त सुविधाओं की राजनीति का कोई दल विरोध नहीं करता। तिस पर आज का जो असहिष्णु राजनीतिक माहौल है, उसमें इस मुद्दे पर तमाम पार्टियों के साथ एक साथ होने की उम्मीद दूर-दूर तक नहीं है। यानी अदालत द्वारा फ्रीबीज की परिभाषा तय न करने तक चुनावी राजनीति की कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी ही पड़ेगी।

भारत-अमेरिका मैत्री से विकास के नये रास्ते खुलेंगे

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल में सम्पन्न हुई अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक, अविस्मरणीय एवं मील का पत्थर बनकर प्रस्तुत हुई है। यह निश्चित है कि मोदी के नेतृत्व में एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति गढ़ी जा रही है। व्हाइट हाउस में संपन्न प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत कई मायनों में सकारात्मक एवं परिणामकारी रही। उसमें किसी तरह की तल्खी नजर नहीं आई, बल्कि मोदी-ट्रंप की दोस्ती ही नये विश्वास एवं संकल्प के साथ उभर कर सामने आयी है। यह निर्विवाद सत्य है कि अमेरिका हमेशा अपने कारोबारी हितों को ही प्राथमिकता देता है। इस मुलाकात में यही नजर आया कि ट्रंप दोनों देशों के व्यापार संतुलन का पलड़ा अमेरिका के पक्ष में करने को कटिबद्ध है। लेकिन मोदी ट्रंप की चतुराई को भी अपनी सादगी एवं सरलता से मात देते हुए भारत के हित में अनेक समझौते कर लिये हैं। यह तथ्य सर्वविदित है कि अमेरिका की नीतियां 'अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका' पर ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप ने जिस आक्रामक तरीके से कनाडा, मैक्सिको व चीन आदि पर टैरिफ लगाए हैं, वैसी आक्रामकता उन्होंने भारत के प्रति नहीं दिखायी। यह अमेरिका की भारत के प्रति एक विशेष दृष्टि मोदी के प्रभाव का ही परिणाम है।

ट्रंप ने मोदी को अपनी तुलना में बेहतर सख्त वार्ताकार बताया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने तथा लाभप्रद व्यापार समझौते के लिये बातचीत करने का संकल्प भी जताया। भविष्य में व्यापार समझौता अमेरिका के पक्ष में न झुके, इसके लिये प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। भारत को नया बनने के लिए, स्वर्णिम बनाने के लिए, अनूठा बनाने के लिए और उसे विश्व की एक बड़ी ताकत के रूप में उभारने के लिये मोदी के प्रयास अनूठे भी हैं और विलक्षण भी हैं। यहां उल्लेखनीय है कि मोदी-ट्रंप मुलाकात में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बातचीत सकारात्मक रही। दोनों देशों ने एक दस वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसमें प्रमुख हथियारों और प्लेटफार्मों के सह-उत्पादन को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना का मार्ग प्रशस्त किया गया। वहीं दूसरी ओर यदि भारत को अमेरिकी एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित आपूर्ति परवान चढ़ती है तो पड़ोसी देशों की बेचैनी और बढ़ जाएगी और भारत की ओर देखने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। मोदीजी का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोला है। मोदी की इस यात्रा के पीछे इरादा केवल भावनात्मक रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करना नहीं रहा है, बल्कि भारत के हक में अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए उनका सहयोग पाने की मंशा भी रहा है, जो सफल हुआ। संभव है इससे भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में विकास के नये रास्तें खुलेंगे।

इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा यह भी रही है कि 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। यह पाकिस्तान को चेतावनी भी है कि वह अपनी जमीन से आतंकवादियों को सीमापार आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद बंद करे। अब इस्लामाबाद पर मुंबई और पठानकोट के आतंक हमलों के साजिशकर्ताओं को सजा देने का दबाव भी बढ़ जाएगा। निस्संदेह, ट्रंप का 'टैरिफ आतंकवाद' निगलने वाली कड़वी गोली हो सकती है, लेकिन भारत की रक्षा

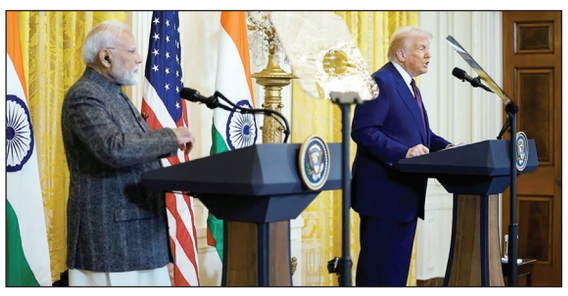

तैयारियों में अमेरिका की बड़ी भूमिका एक आकर्षक प्रस्ताव होगा, जिससे भारत सैन्य मोर्चे पर सशक्त होकर उभरेगा। ट्रंप के साथ मुलाकात में भारत ने अवैध रूप से आए भारतीयों को वापस लेने की बात भी कही। पत्रकार वार्ता में मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं। यदि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की पुष्टि होती है तो हम उन्हें वापस लेने के लिये तैयार हैं। उन्होंने इसे मानव तस्करों की करतूत बताया।

मोदी की यह यात्रा दो बहुत अच्छे दोस्तों की बहुत ही नाजूक समझौतेवादी भूमिका को देखने का एक दिलचस्प एवं रोमांचक मौका बनी, प्रतिकूल लगते हालात को अनुकूल नतीजों की ओर मोड़ने का कौशल भी इस यात्रा में बेहतरीन अंदाज में नजर आया। दोनों नेता न केवल पहले से एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते रहे हैं बल्कि उनके बीच की व्यक्तिगत मित्रता एवं आत्मीयता भी चर्चित रही है। यह सुखद संयोग है कि दोनों नेता दुनिया के सबसे बड़े पुराने और सबसे विशाल लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका को पहले से ही दुनिया ग्लोबल लीडर मानती रही है। अब भारत नया और उभरता हुआ विश्वनेता बना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जोड़ी से दुनिया पर नये तरीके से आधिपत्य बदलता दिख रहा है। दोनों देशों के लगातार बेहतर होते रिश्तों की पृष्ठभूमि इस तथ्य को और महत्वपूर्ण बना रही थी। फिर भी यात्रा से पहले के घटनाक्रम ने इसकी कामयाबी पर भले ही संदेह की परतें चढ़ा रखी थी, लेकिन मोदी की कुशलता एवं कूटनीति से सभी वार्ताएं सौहार्दपूर्ण होकर सकारात्मक बनी। जिससे भारत एक बार फिर दुनिया के सामने सशक्त एवं ताकतवर बनकर ही प्रस्तुत हुआ है।

ट्रंप के कतिपय सख्ती से बने तनाव को मोदी ने हावी नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से अपने अजेंडे पर केंद्रित रहे। उन्होंने न केवल ट्रंप की तारीफ की बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रिय नारे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (एमएजीए) की तर्ज पर अपना नारा पेश किया- 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' (एमआईजीए), और यह भी कहा कि जब एमएजीए और एमआईजीए साथ आते हैं तो बन जाता है एमईजीए जो दोनों देशों की शानदार साझेदारी की कहानी कहता है। इस तरह दोनों देश ने दुनिया के बॉस होते हुए अपने वर्चस्वी होने को व्यक्त किया। अमेरिका तो इस भूमिका में रहा है, लेकिन अमेरिका भारत को भी इस भूमिका में मानता है तो निश्चित ही यह भारत की दुनिया में मजबूत होती स्थिति को ही बयां कर रहा है। अब दुनिया के हर विवादों को सुलझाने में भारत-अमेरिका की संयुक्त एवं भूमिका महत्वपूर्ण होने से भारत की ताकत को समझा जा सकता है। निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच के कई समीकरण आने वाले दिनों में नया आकार लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इस उम्मीद को ठोस आधार दे दिया है कि सहयोग के स्वरूप में जो भी बदलाव हो, रिश्ता बेहतर ही होता जाएगा। मोदी की इस अमेरिका यात्रा की अहमियत जाहिर है और इसे संभावनाभरा भी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह अमेरिका का उनका पहला सफर है। ट्रंप के साथ वाइट हाउस में मोदी की मुलाकात ने यही जताया कि दोनों नेताओं एवं देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ललक दोनों तरफ है।

भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात पर देश ही नहीं, दुनिया की भी निगाहें थीं। एक तो इसलिए कि मोदी उन चुनिंदा शासनाध्यक्षों में से एक हैं, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रारंभिक दौर में ही मुलाकात करना बेहतर समझा और दूसरे इसलिए कि भारत अब एक बड़ी ताकत बन चुका है और वैश्विक मामलों में उसका रुख-रवैया एवं नीतियां मायने रखती है। इस मुलाकात को लेकर जिज्ञासा का एक कारण यह भी था कि बाइडन प्रशासन के समय अमेरिका और भारत के संबंधों में एक खिंचाव आ गया था। एक अर्से से यह महसूस किया जा रहा था कि बाइडन प्रशासन भारतीय हितों की वैसी चिंता नहीं कर रहा है, जैसी करनी चाहिए। मोदी और ट्रंप की मुलाकात ने यह तो रेखांकित किया कि दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी लौट आई है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका भारत की समस्त चिंताओं का समाधान करने जा रहा है, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा रहा है। ट्रंप ने बांग्लादेश के मामले में भारत के मन मुताबिक बात कहकर, सीमा पार यानी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से मिलकर लड़ने का वादा किया। कुल मिलाकर विकसित भारत के लक्ष्य में सहायक बनने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका से सहयोग की राह प्रशस्त होना भारत के लिये एक नये सूरज का उदय ही कहा जायेगा।

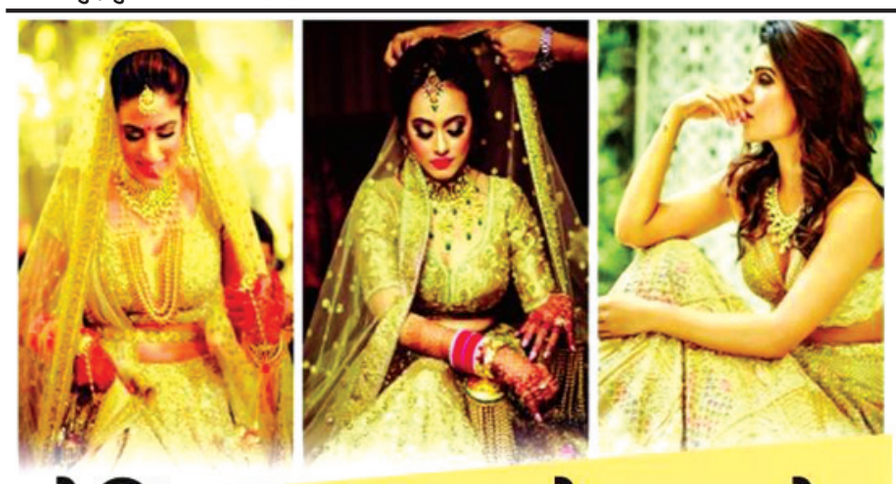

वेडिंग फंक्शन्स में आपको स्टाइलिश दिखाएंगे ये टिप्स

वेडिंग में कई फंक्शन्स होते हैं, जिनके लिए अलग-अलग ड्रेसेस पहनने का मजा ही कुछ और है। इनमें हल्दी फंक्शन का क्रेज लड़कियों के बीच खूब देखा जाता है। हल्दी के दौरान पीले कपड़े पहनने से न सिर्फ फैशन के नजरिए से कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है बल्कि पीले रंग के साथ ज्यादातर ज्वैलरी भी अच्छी लगती हैं। आप भी अगर अपनी हल्दी पर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो ये टिप्स आपके काम आएंगे।

हल्दी सेरेमनी पीले रंग के कपड़े क्यों पहनें

हल्दी छुड़ाना काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए क्यों न इस दिन पीली ड्रेस ही पहनी जाए। पीले के अलग-अलग शेड्स में से आप चुन सकती हैं। मस्टर्ड येलो, ऐंबर येलो, लेमन येलो में से आप चुन सकती हैं। यदि आपको येलो नहीं पहनना हो, तो आप क्रीम या कोई और लाइट कलर पहन सकती हैं।

हल्दी सेरेमनी के लिए टिप्स

- अगर आपकी हल्दी सेरेमनी है, तो ऐसे में आप स्लीव्स कट सिंपल और प्लेन लहंगा-चोली पहनें, जिसके किनारे पर गोल्डन या सिल्वर कलर का बॉर्डर हो।
- हल्दी सेरेमनी पर पटियाला सलवार के साथ शार्ट कॉटन कुर्ती भी बेहद स्टाइलिश लगेगी। पटियाला सूट के साथ आप अपनी पसंदानुसार एम्ब्रॉयडरी जैकेट या फिर कोई लाइट दुपट्टा कैरी करना अच्छा ऑप्शन रहेगा।
- आपको अगर साड़ी पहननी है, तो पीले रंग की सिम्पल साड़ी पहनें या फिर लाल, नारंगी रंग की साड़ी भी काफी अच्छी लगेगा। इसके साथ मैचिंग पर्ल ज्वैलरी या फूलों की ज्वैलरी भी काफी ट्रेंडिंग लगेगी।

हैवी दुपट्टा

हल्दी के मौके पर दुपट्टा आपके लिए आफत बन सकता है, इसलिए लाइट स्टोल या स्कॉर्फ तक ठीक है लेकिन हैवी दुपट्टा लेने से बचें।

स्टोन, हैवी ज्वैलरी

स्टोन या हैवी ज्वैलरी पर अगर हल्दी लग गई, तो आपके लिए खासी दिक्कत हो जाएगी।

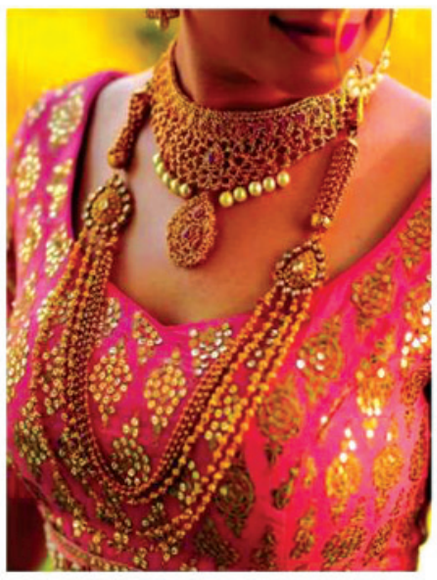

दमकती त्वचा का सपना पूरा करेंगे इन फलों के छिलके

आज तक आपने अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए फलों को डाइट में शामिल करने की सलाह तो कई बार सुनी होगी पर क्या आप जानते हैं फल अगर आपको अच्छी सेहत पाने में मदद करते हैं तो फलों के छिलके आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं दमकती त्वचा पाने के लिए कैसे करें फलों के छिलकों का इस्तेमाल।

पपीते का छिलका

चेहरे का रूखापन दूर करके त्वचा का ग्लो बढ़ाने का काम करता है पपीते का छिलका। इसके लिए पपीते के छिलके को सुखाकर बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब दो चम्मच पाउडर में एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर उसे अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह लगा लें। पैक सूख जाने पर अपना चेहरा धो लें। चेहरे की टैनिंग हटाने के लिए पपीते के छिलके को पीसकर उसमें नींबू का रस मिला का इस्तेमाल करें।

संतरे का छिलका

चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे, मुहांसों और टैनिंग से निजात पाने के लिए संतरे के छिलके को पीसकर उसका बारीक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में 2 चम्मच कच्चा दूध और दो चुटकी हल्दी मिलाकर इस पेस्ट को फेस पैक की तरह चेहरे पर लगाएं। पैक सूखने पर चेहरे ठंडे पानी से धो लें।

नींबू का छिलका

टैनिंग दूर करने के लिए नींबू के छिलके को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें।

केले का छिलका

टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए आप केले के छिलके के अंदरूनी सफेद भाग को चेहरे पर हल्के हाथों से बीस मिनट तक रगड़ें। इसके बाद चेहरा धो लें। ऐसा करने से चेहरे की चमक बढ़ती है।

आम का छिलका

चेहरे की झुर्रियों को कम करने के लिए आम के छिलके को पीसकर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से मुहांसों और झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आम के छिलके को सुखाकर इसका पाउडर बना कर गुलाब जल के साथ, गेहूं के आटे में मिलाकर चेहरे पर उबटन की तरह इस्तेमाल करें।

कई लोग अपनी हाइट से नाखुश रहते है, उन्हें लगता हैं कि वे थोड़े और लंबे होते तो अच्छा होता। लेकिन अगर कम व अवरेज हाइट होने पर भी सही ड्रस व कपड़ों का चयन करें तो छोटी हाइट को भी लंबा दिखा सकते हैं। आइए, हम आपको कपड़ों के चयन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो छोटी हाइट को लंबा दिखाने में कारगर साबित होंगी -

छोटी हाइट होने पर कैसे करें कपड़ों का चयन

- ऐसी ड्रेस पहनें जिसमें पैर दिखें तो आप लंबी नजर आएंगी जैसे ऐसी कोई शॉर्ट ड्रेस, जो घुटने तक या उससे ऊपर हो। इस तरह की ड्रेस पहनकर छोटे कद को लंबा दिखाया जा सकता है।
- अगर आपका कद छोटा है तो आप हाई वेस्ट की जींस पहन सकती हैं। इस जींस में आपके पैर लंबे नजर आएंगे जिससे देखने वालों को आपकी लंबाई अधिक होने का एहसास होगा।
- छोटे कद को लंबा दिखाने के लिए ऐसे कपड़ों का चयन करें जो वी नेक के हो, जैसे वी-नेक वाली शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ती व ड्रेस आदि। गोल गले के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए।
- कद को लंबा दिखाने के लिए सर से पैर तक एक ही रंग के कपड़ें पहनें, जैसे टॉप और बॉटम दोनों का एक ही रंग होने पर आपका कद लंबा नजर आएगा। वैसे छोटे कद पर गहरे रंग के कपड़ें भी देखने वालों को लंबा होने का एहसास देते है।
- गाउन पहनकर भी आप लंबी नजर आ सकती हैं।
- कपड़ों के अलावा हाई हील्स पहनकर भी आप हाइट को बढ़ा हुआ दिखा सकती हैं।

ट्रेंडी हैं को-ऑर्ड्स इस समर शॉपिंग लिस्ट में करें शामिल

गर्मियों में कम्फर्टेबल आउटफिट्स खरीदना चाहती हैं तो को-ऑर्ड्स ट्राई करें। ये आउटफिट गर्मियों के लिए फिट होने के साथ बेहद स्टाइलिश भी है। गर्मी के मौसम में को-ऑर्ड्स फैशन जबरदस्त ट्रेंड में है। इसको पहनने के कई फायदे हैं। इन्हें पहनने में झंझट नहीं होता, गर्मियों के हिसाब से कम्फर्टेबल है वहीं स्टाइल के मामले में भी नंबर वन। इन टू-पीस सेट्स के साथ आपको ज्यादा अक्सेसरीज भी कैरी करने की जरूरत नहीं। अगर आप अभी भी इस फैशन को ट्राई करने में झिझक रहे हैं तो बॉलिवुड सिलेब्स से आइडिया ले सकते हैं।

बच्चों की मजबूत इम्युनिटी के लिए जन्म के पांच साल के अंदर जरूरी है ये वैक्सीनेशन

कहते हैं हेल्थ एक प्रोसेस है। आप एक दिन में हेल्दी नहीं होते। कई छोटी-छोटी चीजें आपको मजबूत बनाती हैं। यही बात इम्युनिटी पर भी लागू होती है। मजबूत इम्युनिटी हमारे बचपन के खान-पान पर भी निर्भर करती है। वहीं, बचपन में कुछ ऐसे टीके होते हैं, जिनके लगने से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। आज हम आपको ऐसे टीके बता रहे हैं, जिन्हें पांच साल के अंदर बच्चों को लगवाना बहुत जरूरी है।

ये टीके हैं बेहद जरूरी

- गर्भवती महिला एंव गर्भ मे पल रहे शिशु को टिटेनस की बीमारी से बचाने के लियेटिटेनसटाक्साइड 1 / बूस्टर टीका और दूसरा टीका एक महिने के अंतर में लगवाएं। अगर पिछले तीन वर्ष मे दो टीके लगे हों तो केवल एक टीका लगवा लेना ही काफी होता है।
- हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से लीवर की सूजन आ जाती है, पीलिया हो जाता है और लंबे समय तक संक्रमण के बाद लीवर कैंसर का भी खतरा हो सकता है। यह टीका बेहद जरूरी है जो हिपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचाव करता है।
- डीपीटी टीकों की एक श्रेणी होती है, जो इंसानो को होने वाले तीन संक्रामक बीमारियों डिफ्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस से बचाव के लिए दिए जाते हैं।
- पोलियो का टीका पोलियो नामक बीमारी जिसमें बच्चे अपंग हो जाते हैं, से सुरक्षा प्रदान करता है। यह टीका भी बच्चों को जरूर लगवाना चाहिए।
- बच्चे को टीबी से बचाने के लिए अनिवार्य रूप से बी सी जी का टीका लगवा दें। बीसीजी का टीका लग जाने पर शिशु को टीबी की बीमारी से बचाया जा सकता है।
- हिब वेक्सीन का टीका बच्चों को डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस-बी और एच इन्फलांजी-बी से सुरक्षित रखता है। हिब बेक्टीरिया के संक्रमण से न्यूमोनिया एवं मष्तिष्क ज्वर (मेनिनजाइटिस) जैसी गंभीर बीमारी हो सकती हैं।

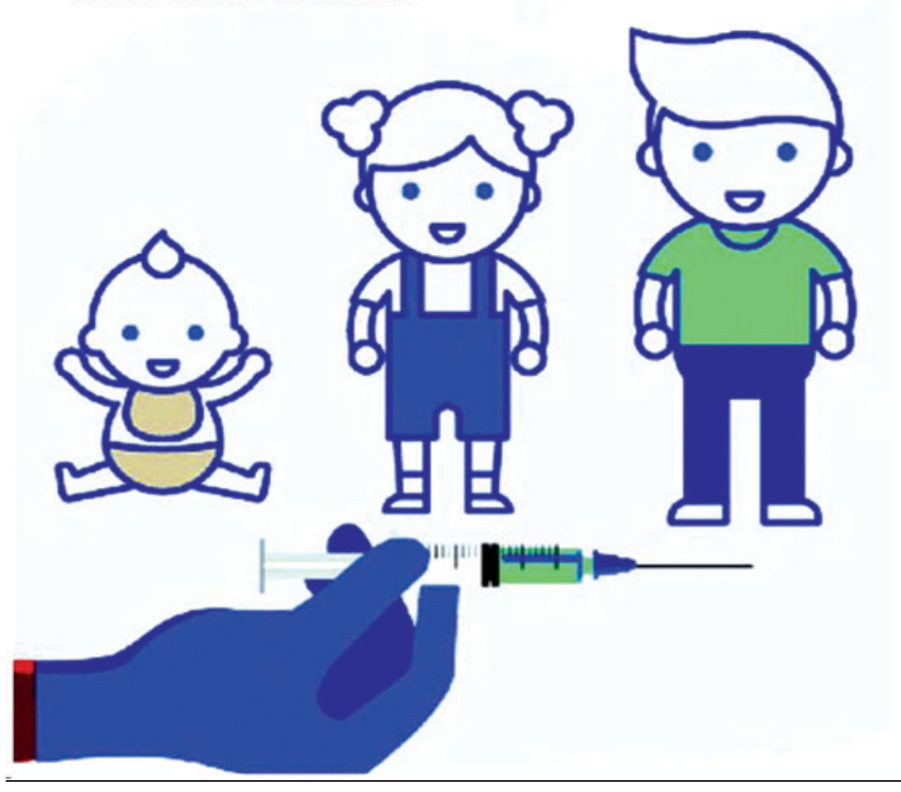

बच्चों से लालच देकर कोई काम न कराएं

'आप अगर खाना नहीं खाओगे, तो रात में भूत आ जाएगा।' क्या आपने भी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए ऐसा ही कोई बहाना बनाया है? आपका जवाब अगर हां है, तो आपको यह बात समझने की जरूरत है कि कभी-कभी हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के लिए कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जिससे कि उनके मन में कई डर घर कर जाते हैं। इसके अलावा बच्चे अनजाने में ही कई गलत आदतें सीख जाते हैं। इस कारण आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए-

आमतौर अपनी बात मनवाने के लिए माता-पिता बच्चे को कोई लालच देते हैं। जैसे होमवर्क पूरा करने या बाहर न जाने के बदले उसे आइसक्रीम या खिलौने का लालच। ऐसा करना बेहद गलत है क्योंकि इसके बाद भी बच्ची सही बर्ताव करने के बदले आपसे अपनी डिमांड को पूरा करवाने की कोशिश करेगा।

किसी के सामने कोई एक्टिंग करने के लिए कहना

आमतौर पर माता-पिता बच्चों को कोई डांस या एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। ऐसा करना शायद एंटरटेनिंग लगे, लेकिन इससे बच्चों के दिमाग पर गलत असर पड़ता है। बार-बार ऐसा कहने पर बच्चे को लगने लगता है कि अगर वह ये सब नहीं करेगा, तो उसके मम्मी-पापा उसे प्यार नहीं करेंगे या फिर मारेंगे।

किसी के सामने बच्चों पर न चिल्लाएं

अधिकतर माता-पिता बच्चों को किसी मॉल में, पब्लिक प्लेस में या फिर किसी पार्क में ही डांटना शुरू कर देते हैं।

इस दौरान बच्चा आपकी बातें न सुनकर वो इस बात पर ध्यान देने लगता है कि आसपास के लोग सुन रहे हैं इसलिए हमेशा बच्चे को एकांत में उसके व्यवहार के बारे में बताएं ताकि वे अपने बुरे व्यवहार को छोड़ सके।

दूसरे बच्चों से तुलना

अपना बच्चा सभी को प्यारा लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चे को फील गुड कराने के लिए उसकी तुलना दूसरों बच्चों से करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए माता-पिता किसी बच्चे को बुरा बताते हुए अपने बच्चे की तुलना करते हैं। ऐसा करने से आपका बच्चा उस दूसरे बच्चे के लिए मन में नेगेटिव इमेज बना लेगा। आगे चलकर यह नेगेटिव चीज उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन सकती है।

गलती करने पर गुस्सा करना

कभी-कभी मां-बाप अपने ऑफिस का गुस्सा या किसी और बात का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। साथ ही माता-पिता गुस्से में अपने बच्चे को उस गलती की सजा दे देते हैं, जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। बच्चे को अनुशासन सिखाते वक्त अपनी दूसरी समस्याओं और गुस्से को अलग रखें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कुर्सी, एसी, टीवी सब उठा ले गए मनीष सिसोदिया?

नईदिल्ली। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने इलाके के विधायक कार्यालय से सभी सरकारी संपत्तियां (वस्तुएं) चुरा ली हैं। उन्होंने दावा किया, उन्होंने एसी, टेलीविजन, कुर्सियां, पंखे, एलईडी और सब कुछ ले लिया है। एक्स पर पोस्ट में विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया था। विधानसभा कैंप कार्यालय से जिसमें एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चुराए गए। इनकी भ्रष्टाचार की हदें अब भी पार नहीं हुईं। अब वे अपनी असलियत छुपाने और चोरी करने की राजनीति में माहिर हो गये हैं। हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और ऐसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करेंगे। नेगी ने खाली विधायक कार्यालय वाली वीडियो क्लिप भी एक्स पर पोस्ट की है।

ज्ञानेश के सीईसी बनने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

नईदिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अधिकारी के नाम की सिफारिश करने वाले पैनल की संरचना की सुप्रीम कोर्ट की जांच को दरकिनार करने की इच्छुक थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार रात को एक्स पर लिखा, यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दोहराया है - चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए, सीईसी को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित कानून ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को सीईसी चयन पैनल से हटा दिया है।

भारत और कतर के बीच कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। इससे पहले कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कतर के अमीर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमीर अल थानी का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। इसके बाद अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी को सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मिलवाया गया। कतर के अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बैठक करेंगे। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया जाएगा। अमीर अल-थानी 17 फरवरी की रात को भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद कतर के अमीर का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे।

बसपा ने विवादित टिप्पणी को लेकर उदित की आलोचना की

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने मायावती के खिलाफ विवादित टिप्पणी और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में आनंद ने राज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, आज लखनऊ में माननीय कांशीराम साहब के कुछ पुराने साथी, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के चाटुकार उदित राज ने साहब के मिशन पर बात की। उन्होंने कहा, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों में अवसर तलाशने के लिए कुख्यात हैं। उन्हें बहुजन आंदोलन की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वे किसी पार्टी से सांसद या विधायक बन सकें। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह अस्वीकार्य है। आनंद ने कहा, मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को उनसे ज्यादा समझता हूं।

शिंदे सेना के 20 विधायकों की सुरक्षा में कटौती : सूत्र

मुंबई। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार बढ़ने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन गृह विभाग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 20 विधायकों की वाई-सुरक्षा वापस ले ली है। हालांकि भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ विधायकों की सुरक्षा भी कम की गई है, लेकिन यह संख्या शिवसेना के विधायकों से काफी कम है। इस कदम को राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की पहल के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि इन विधायकों को वाई-सुरक्षा कवर एक अतिरिक्त भत्ते के रूप में दिया गया था, जबकि वे मंत्री नहीं हैं। यह इन विधायकों को 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग होने के बाद प्रदान किया गया था, जिसके कारण अंततः महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मुहर

केजरीवाल भी रह जाएंगे हैरान

नईदिल्ली। दिल्ली में नई सरकार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह इस बार भी रामलीला मैदान में होगा। शपथग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी की रात से बंद होंगे ताकी 20 फरवरी को शपथग्रहण समारोह हो सके। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की टाइमिंग बदल गई है। पहले जहां 20 फरवरी की शाम 4.30 बजे दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण होना था तो वहीं अब यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना निश्चित हुआ है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कार्यवाहक सीएम आतिशी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा है कि दिल्ली को चलाने के लिए बीजेपी के पास सीएम का चेहरा तक नहीं है। वहीं अब इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बैचेन है। दिल्ली को लेकर दो -तीन दिन सब कुछ हो जायेगा। हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा होगा।

चुनाव हुए तो पहले परवेश वर्मा का नाम हर किसी की जुबान पर था। उन्होंने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर मात दी बल्कि वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए सांसद मनोज तिवारी का नाम राजनीतिक गलियारों में काफी उछल रहा है। पूर्वांचल का बड़ा नाम होने के कारण ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने कहा कि सीएम के नाम पर सस्पेंस जल्द खत्म होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के कयास जल्द ही खत्म होने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय अनुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली को मिलने वाला है। रामलीला मैदान में होने वाले शपथग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी समेत 150 लोगों को न्यौता पहुंचा है। एनडीए के नेताओं को रामलीला मैदान में जुटा शक्ति प्रदर्शन भी किया जा सकता है।

मनोज तिवारी ने खुद भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी इच्छा जता चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि चेहरा तो हम हैं, वो भी तीसरी बार। साथ ही और भी चेहरे हैं। दिल्ली में अगर एक जगह से तीसरी बार अगर टिकट दिया गया तो वो पूर्वांचली ही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को वो सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूं।

बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसके बारे में तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी पहले भी फेल होती रही है। मोदी-शाह की तरफ से फैसले चौंकाने वाले ही होते रहे हैं। लेकिन तमाम किंतु-परंतु से इतर मनोज तिवारी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। पूर्वांचली वोट बैंक, बिहार चुनाव और खुद मनोज तिवारी की इच्छा, ये सभी फैक्टर उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे रखते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने कहा

सपा ने सरकार के बहुत अच्छे कामों का विरोध किया

लखनऊ। यूपी विधानसभा बजट सत्र- उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र की शुरुआत से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महाकुंभ भगदड़, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। बाद में सदन को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि उनकी सरकार विपक्ष द्वारा पूछे जा रहे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। योगी ने कहा कि सपा को राज्य सरकार द्वारा किए गए हर काम का विरोध करने की आदत है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। 20 फरवरी को सदन में उत्तर प्रदेश का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जाएगा। सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं, जब इतने लंबे समय तक सत्र आहूत किया गया हो। लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से पूरी होनी चाहिए। यह केवल सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सदन चर्चा का मंच बनना चाहिए।

योगी ने कहा कि पिछले करीब 8 वर्षों में डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो मानक स्थापित किए हैं, वे अभूतपूर्व हैं। इसकी झलक राज्यपाल के अभिभाषण के साथ-साथ सदन के अंदर होने वाली चर्चाओं से भी मिलती है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने की कोशिश करता है और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है।

योगी ने बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का आग्रह किया इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से आगामी बजट सत्र के दौरान सदन में जनहित के मुद्दे उठाने और विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने को कहा। बजट सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सदन के नेता योगी ने बैठक में नेताओं से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि सदन के कामकाज में कोई बाधा न आए और वे जनहित से जुड़े हर मुद्दे को उठाएं।

उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने और सदन को सुचारू रूप से चलाने से विकास को गति मिलेगी। स्पीकर सतीश महाना ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग करने की भी अपील की। एक बयान में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के विनोद सरोज भी अन्य लोगों के साथ मौजूद थे।

सीएम ने सोमवार को विधान भवन के मुख्य द्वार का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर की दीवारों पर भित्ति चित्रों का अनावरण भी किया गया। भित्ति चित्रों में राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं को उकेरा गया है। इनमें गीता के विभिन्न प्रसंगों को भी दर्शाया गया है। यूपी सरकार ने एक बयान में कहा कि विधान भवन के लकड़ी के गेट को अत्याधुनिक और नक्काशीदार स्टील के मजबूत गेट से बदल दिया गया है। बयान में कहा गया है कि विधानसभा का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसे तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के साथ-साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

महाकुंभ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ 2025 को मृत्यु कुंभ बता दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह महाकुंभ का सम्मान करती हैं। बनर्जी ने कहा, यह मृत्यु कुंभ है..मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं। लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है, कितने शव बरामद हुए हैं? अमीरों, वीआईपी लोगों के लिए एक लाख रुपये तक के शिविर पाने की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई है? राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के भाषण पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कई राज्यों में डबल-इंजन सरकार है, जहां डबल-इंजन सरकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने विपक्ष को (बोलने के लिए) 50 फीसदी समय दिया। उन्होंने सदन के पटल पर कागज फेंके। भाजपा, कांग्रेस और माकपा एक साथ मेरे खिलाफ हैं। उन्होंने मुझे अपना भाषण नहीं देने दिया। मुख्यमंत्री बनर्जी ने विधानसभा में कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बोलना या किसी धर्म के खिलाफ भड़काना नहीं है। आप एक धर्म विशेष को बेच रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, जहां वह (विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी) हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए उन्हें सदन से निलंबित किया गया है। मैं कभी धार्मिक मामले को भड़काने की बात नहीं करती है।

खेल
प्रमुख समाचार

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का आज से आगाज

नईदिल्ली। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की साल 2017 के बाद वापसी हो रही है और बुधवार से टूर्नामेंट का आगाज होगा जिसमें 8 टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा लेकिन भारत अपने सभी मैच हाईब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान गत चैम्पियन है ऐसे में वह 19 फरवरी को टूर्नामेंट की शुरूआत करेगा और पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलेगा। वहीं भारत अपने अभियान की शुरूआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी का हाई-वोल्टेज मैच 23 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में होगा।

ग्रुप- ए की टीमें

बांग्लादेश : नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), सौम्य सरकार, तन्जीद हसन, तौहीद हृदोय, मुश्फिकुर रहीम, मोहम्मद महमुदुल्लाह, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन, नसुम अहमद, तन्जीम हसन साकिब, नाहिद राणा।

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रवींद्र जड़ेजा, वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड : मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, विल ओ%रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, केन विलियमसन, विल यंग।

पाकिस्तान : मोहम्मद रिजवान (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 47 अंक टूटा निफ्टी 22,945 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार (18 फरवरी) को एक बार फिर गिरावट में बंद हुए। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान बाजार आधा प्रतिशत से ज्यादा गिर गया था। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 76.85 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 76,073 पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान यह 75,531 अंक तक गिर गया था। अंत में सेंसेक्स काफी हद तक रिकवर करते हुए 45.78 अंक या 0.06% गिरकर 75,951 पर लगभग सपाट बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी आज मामूली बढ़त के साथ खुला। हालांकि, खुलते ही यह लाल निशान में चला गया और कारोबार के दौरान 22,801 के स्तर तक फिसल गया था। अंत में इंडेक्स 14.20 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट लेकर 22,945.30 पर बंद हुआ।

टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश का संकेत दिया

नयी दिल्ली। लिंक्डइन पर एक जॉब पोस्टिंग के अनुसार टेस्ला इंक ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है, जो इस बात का एक मजबूत संकेत है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। यह टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा हाल ही में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ समय बाद हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला ने भारत में 13 नौकरियों के अवसर सूचीबद्ध किए हैं, जो ग्राहक-सामना और बैक-एंड दोनों भूमिकाओं को कवर करते हैं। सोमवार को कंपनी के लिंक्डइन पेज पर जॉब पोस्टिंग देखी गई। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला ने भारत में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां शुरू की हैं। इनमें व्यवसाय संचालन विश्लेषक और ग्राहक सहायता विशेषज्ञ शामिल हैं, जो कंपनी के देश में प्रवेश के लिए एक अग्रदूत हो सकता है।

अगले कुछ महीनों में हो जाएगा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक 500 अरब डॉलर तक लेकर जाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत व्यापार समझौते पर अगले 6-8 महीने बातचीत होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि अभी अमेरिका में उनके समकक्ष मंत्री ने पद नहीं संभाला है, जैसे ही वे पद संभालेंगे, तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत की जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए समर्पित हैं। पीयूष गोयल ने भारत-कतर बिजनेस फोरम की बैठक से इतर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के व्यापार जगत के लोग इस सौदे को लेकर उत्साहित हैं।

सीफूड बेचने वाली लिसियस स्टॉक मार्केट में करेगी एंट्री!

नईदिल्ली। भारत में ऑनलाइन मीट और सीफूड बेचने वाली कंपनी लिसियस अगले साल यानी 2026 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कपंनी प्रॉफिटेबल होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लिसियस में Temasek Holdings Pte ने अहम निवेश किया है। इसका ऑपरेशन Delightful Gourmet Pvt करती है। लिसियस के सीईओ और सह-संस्थापक विवेक गुप्ता ने कहा, हम अगले 12 महीनों में आईपीओ के लिए पूरी तरह तैयार कंपनी बनना चाहते हैं। कंपनी नए ऑफलाइन स्टोर्स खोलने, डिलीवरी तेज करने और क्रिक कॉमर्स कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य अगस्त 2025 तक EBITDA स्तर पर लाभदायक बनना है।

वित्तमंत्री ने आयकर की सीमा बढ़ाकर मध्यम तबके को दी राहत

पी. चिदंबरम

एक तमिल कहावत है- यदि भूख लगेगी तो दस गुण खत्म हो जाएंगे। ये दस गुण हैं- सम्मान, कुल, शिक्षा, उदारता, ज्ञान, दान, तपस्या, प्रयास, दृढ़ता और इच्छा।

आधुनिक समय में चुनाव के समय ये दस और अन्य कई गुण भी गायब हो जाते हैं। देश का बजट 2025-26 दिल्ली चुनाव की पूर्व संध्या और बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले पेश किया गया। मैंने शायद ही कभी ऐसा बजट देखा हो, जिसमें सरकार सिर्फ जनता का वोट जीतने के लिए वह सब कुछ दे दे, जो वह एक साल में कुछ लोगों को ही दे सकती है। माननीय वित्त मंत्री ने बजट में बिल्कुल यही किया है।

वित्त मंत्री ने इस बात का हिसाब लगाया कि उनके पास एक लाख करोड़ रुपये का खजाना है। उन्हें पैसे मिले और उन्होंने सोचा कि इसे 143 करोड़ की आबादी में से आयकर देने वाले 3.2 करोड़ लोगों में बांटा जाए। इन 3.2 करोड़ आयकर दाताओं में मध्यम वर्ग, अमीर, बहुत अमीर और अति अमीर, सभी शामिल हैं। इसने तमिल कहावत में शामिल दस गुणों के साथ-साथ सामाजिक न्याय, समता और वितरणात्मक निष्पक्षता जैसे शासन के आधुनिक मूल्यों को भी हवा में उड़ा दिया।

बजट की कवायद जैसे ही शुरू हुई, वित्त मंत्री गिरते राजस्व के दबाव में थीं। वित्त मंत्रालय का अनुमान था कि केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां 2024-25 के बजट अनुमान से लगभग 60 हजार करोड़ रुपये कम हो जाएंगी। इसके अलावा अगर वित्त मंत्री 2024-25 के राजकोषीय घाटे में सुधार करना चाहतीं तो वित्त मंत्रालय को कम से कम 43 हजार करोड़ रुपये जुटाने होते। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब एक लाख

करोड़ रुपये जुटाने थे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव नजदीक थे और यदि ऐसे में उपहारों पर विचार किया गया तो 2025-26 में अतिरिक्त धन की जरूरत होगी।

यह बहुत मुमकिन है कि आयकर में कटौती का 'उपहार' सरकार के उच्चतम स्तर पर तय किया गया था। करदाताओं के किस वर्ग को लाभ मिलना चाहिए? ओह बकवास (जैसा कि ट्रंप ने कहा होगा), प्रत्येक आयकरदाता को यह मिलना चाहिए! इसलिए कर योग्य आय की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इसकी लागत एक लाख करोड़ रुपये होगी।

एक बार जब ये निर्णय ले लिए गए तो 2024-25 के खर्चों में कटौती करने और 2025-26 में नागरिकों के अन्य वर्गों को किसी भी तरह की राहत देने का कोई विकल्प बचा ही नहीं। मनरेगा श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, गैर-आयकर भुगतान करने वाले वेतन भोगी कर्मचारी, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, एमएसएमई, गृहिणियों, पेंशन भोगी और बेरोजगार युवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया।

वित्त मंत्री ने एक चाल चलते हुए विदेश से लेकर शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण समेत शहरी विकास तक के मंत्रालयों की पूंजी और खर्च, दोनों में बेरहमी से कटौती की। इसके अलावा एक लाख करोड़ रुपये छोड़ने के बावजूद उन्होंने यह मान लिया कि 2024-25 की तरह 2025-26 में भी केंद्र सरकार की प्राप्तियां 11 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी।

पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार, युवा बेरोजगारी 10.2 प्रतिशत और स्नातक बेरोजगारी 13 प्रतिशत है। बजट में रोजगार सृजन की योजनाओं पर खर्च को लेकर आठ लाइनें हैं, जिनमें से पांच लाइनें उत्पादकता से जुड़ी निवेश (पीएलआई) योजनाओं के बारे में हैं। इसका खूब प्रचार भी किया गया। इन आठ लाइनों के लिए 2024-25 का बजट अनुमान (बीई) 28,318 करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान (आरई) केवल 20,035 करोड़ रुपये है। यह रोजगार सृजन कार्यक्रम की भारी विफलता को दिखाता है। घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) 4,226 रुपये और शहरी इलाकों में 6,996 रुपये था।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगा बढ़ावा: सीएम साय

■ आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

■ सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए सीईजीआईएस और टीआरआई के साथ हुआ एमओयू

रायपुर। प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में 'सुशासन एवं अभिसरण विभाग' की स्थापना की है। यह 58वां विभाग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हुए एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को इस पहल से नया आयाम मिलेगा। इस एमओयू से न केवल सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शासन की योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा।

सीईजीआईएस के फाउंडर श्री कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर राज्य की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग देंगे। साथ ही, रणनीतिक बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन में शासन को सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और डेटा-ड्रिवन नीति निर्माण से छत्तीसगढ़ को व्यापक लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए ञ्रञ्छ के साथ हुए समझौते के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। ञ्रञ्छ के एसोसिएट डायरेक्टर श्री श्रीश कल्याणी ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर स्थानीय शासन को सशक्त बनाने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को तेज गति देने में सहयोग करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-आधारित आजीविका और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और राज्य की जनता को योजनाओं का त्वरित और प्रभावी लाभ मिलेगा।

इस ऐतिहासिक समझौते के अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि इस एमओयू की छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, तथा सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अंबिकापुर में डिजिटल भू-प्रबंधन की नई शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू-प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने मध्यप्रदेश के रायसेन से इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस पहल के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू-सम्पत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का त्वरित समाधान होगा और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनेंगे।

अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, कलेक्टर श्री विलास भोसकर, अपर कलेक्टर सुनील नायक एवं नगर निगम कमिश्नर डी. एन. कश्यप समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना शहरी भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी और सम्पत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से सम्पत्तियों का हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे भविष्य में सरकारी दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड में सटीकता लाने के लिए उपयोग किया जाएगा।यह परियोजना देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी को इस योजना में शामिल किया गया है।

पंचायत चुनावों में शानदार जीत भाजपा के प्रति अगाध जन-विश्वास की मुखर अभिव्यक्ति: सौरभ सिंह

जिला पंचायतों के अब तक घोषित 160 परिणामों में भाजपा ने 98 सीटें जीतीं, 17 भाजपा समर्थित निर्दलीय भी जीते

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक सौरभ सिंह ने पंचायत चुनवों के प्रथम चरण के मतदान के बाद सामने आ रहे परिणामों को पार्टी के विश्वास के अनुरूप बताते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी को पूरे प्रदेश में जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जन कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से जनता में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है और ये नतीजे उसी विश्वास की मुखर अभिव्यक्ति हैं।

भाजपा पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक श्री सिंह ने कहा कि प्रथम दौर के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अभी तक जो आँकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनमें 160 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 108 और भाजपा समर्थित 17 निर्दलीय (कुल 125) प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। अन्य क्षेत्रों में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है और उनमें भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की 33 जिला पंचायतों में से 14 जिला पंचायतों में तो कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। बस्तर के नारायणपुर जिला पंचायत के सभी 9 क्षेत्रों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। इसी प्रकार भाजपा के कवर्धा के सभी 6, खैरागढ़ के सभी 5, कोण्डागाँव के सभी 4, मुंगेली के सभी 4, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के सभी 4 जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। बलौदाबाजार के 6 में से 5, जांजगीर-चाँपा के 6 में से 4, बलरामपुर के 6 में से 4, सक्ती के 4 में से 3, रायगढ़ के 6 में से 5 और बालोद के 5 में से 3 क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। इन सभी जिलों के साथ-साथ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा कोरबा में कांग्रेस शून्य पर है और उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है। इनके अलावा शेष जिलों में भी कांग्रेस को इक्का-दुक्का सीटों पर ही जीत मिल सकी है। भाजपा पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक श्री सिंह ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों और सरपंच के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जीतकर आए हैं।

ईडी में 53 अफसरों की पदोन्नति, नीरज सिंह रायपुर पदस्थ

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 53 अफसरों को उप निदेशक (डीडी) पदोन्नत कर स्थानांतरित किया है, जिनमें आरपीजेडओ-2 से नीरज सिंह रायपुर जोनल आफिस में पदस्थ किए गए हैं। उल्लेखनीय हैं कि गत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रायपुर में संयुक्त निदेशक प्रभाकर प्रभात को पदस्थ किया था। इसी तरह से रायपुर सब जोनल आफिस को प्रोन्नत कर नेताजी सुभाष स्टेडियम में जोनल आफिस स्थानांतरित किया गया है। रायपुर ईडी कांग्रेस शासन काल में हुए महादेव सट्टा ऐप, कोल लेवी वसूली, शराब घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाले जैसे मामलों की जांच कर रहा है। इसमें पूर्व मंत्री से लेकर कई कांग्रेस नेता, आईएएस और राप्रसे के अफसर जेल भेजे जा चुके हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाजपा की जबरदस्त जीत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और जनता को दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपना वर्चस्व कायम किया। नारायणपुर, कवर्धा, खैरागढ़, कोंडागांव, मुंगेली और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जैसे जिलों में भाजपा ने सभी सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया। इन नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्रदेश में भाजपा की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।

भाजपा का जलवा अन्य जिलों में भी देखने को मिला, जहां पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की। जांजगीर-चांपा में 6 में से 4, बलरामपुर में 6 में से 4, सक्ती में 4 में से 3, बालोद में 5 में से 3, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 4 में से 2 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने सफलता हासिल की। वहीं, रायगढ़ में 6 में 5, धमतरी में 6 में 5 और कांकेर में 6 में 4 सीटों पर भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों और पारदर्शी प्रशासन पर भरोसा जताया है। यह जीत जनता के आशीर्वाद और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह जीत उसी दिशा में जनता की स्वीकृति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे बताते हैं कि जनता भाजपा की नीति और नेतृत्व पर पूरा भरोसा कर रही है। पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य किए हैं, जनता ने उन पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प है कि गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे और जनता को सुशासन मिले।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि इन नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आने वाले चरणों में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी सफलता मिलेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कुलदीप जुनेजा को कांग्रेस ने भेजा नोटिस, प्रदेश नेतृत्व पर उठाये थे उठाए...

रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आंतरिक कलह गहराने लगी है। जहां एक तरफ पार्टी के भीतर इस्तीफों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर

वरिष्ठ नेताओं ने बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस अब पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के मूड में है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदु ने कहा कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी को मामले की जानकारी दे दी गई है, और जल्द ही पार्टी की ओर से जुनेजा को नोटिस जारी किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कुलदीप जुनेजा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। जुनेजा के अनुसार, उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में केवल आकाश तिवारी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। बावजूद इसके, आकाश तिवारी निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्षद बन गए हैं।

धान खरीदी: महीने भर बाद 1 हजार करोड़ जारी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समाप्त हो चुकी है, जिसमें 25.49 लाख किसानों ने 31 जनवरी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा। हालांकि, खरीदी के दौरान किसानों को

समर्थन मूल्य की राशि मिलती रही, लेकिन 17 से 31 जनवरी के बीच धान बेचने वाले लगभग 17 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नहीं मिल सकी। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होते ही अब किसानों को उनके पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर दो दिन पहले 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए। सूत्रों के अनुसार, सोमवार को करीब एक महीने बाद पुन: 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जबकि अभी भी 2000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 17 से 31 जनवरी के बीच 16,99,596 किसानों ने लगभग 17.42 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था। औसत समर्थन मूल्य के अनुसार प्रति क्विंटल 2300 रुपए की दर से इन किसानों को कुल 3000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। हालांकि, लंबित भुगतान के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सिरसा बांध डुबान क्षेत्र: मालिकों को मुआवजा देने का आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मस्तूरी के सिरसा बांध के डुबान क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कर जिनकी जमीन डुबान में आई है, उन्हें उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश मिलने के 60 दिवस के अंदर यह कार्रवाई करें। मस्तूरी क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा सिरसा बांध का

निर्माण किया गया है। याचिकाकर्ता केरा बाई एवं मुना बाई की भूमि डुबान में आई है। इससे भूस्वामियों ने 2007 से यहां खेती बंद कर दी है। भूमि स्वामियों ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए एसडीओ भू अर्जन, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग सहित अन्य को आवेदन दिया। आवेदन निरस्त होने पर उन्होंने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। याचिका में उन्होंने एसडीओ की सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जमीन का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। जल संसाधन विभाग ने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ताओं की जमीन डुबान में नहीं आने के कारण उनको मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं के पीठ के पीछे कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने एसडीओ भू अर्जन को आदेश प्राप्त होने के बाद 60 दिन के अंदर नए सिरे से सीमांकन कर आदेश करने और यदि याचिकाकर्ताओं की जमीन डुबान में है,तो उन्हें उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है।

लखमा की 4 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक रिमांड

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने

उनकी न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी है।सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कोर्ट से विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं, जिन्हें उन्हें विधानसभा में उठाना है। उनके वकील फैजल रिजवी ने इसके लिए कोर्ट में औपचारिक आवेदन भी दिया। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि यदि विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण वोटिंग हो रही हो, कोई सवाल पूछा गया हो, या लखमा को किसी जवाब के लिए बुलाया गया हो, तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, श्वष्ठ ने यह भी दलील दी कि राज्यपाल की ओर से लखमा को विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और इस पर 20 फरवरी को निर्णय सुनाया जाएगा।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी जिहाद का मामला सामने आया है. नौकरी जिहाद को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने एसएसपी लाल उम्मेद सिंह से मुलाकात की है. वहीं पुलिस और साइबर सेल की टीम मामले की जांच कार्रवाई जारी है. बता दें कि 10 फरवरी को निश्चय वाजपायी ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. निश्चय वाजपेयी ने एसएसपी रायपुर को लिखित शिकायत में बताया था कि ऐसे मामले देवेन्द्र नगर, अभनपुर, धमतरी सहित अन्य थानों में भी दर्ज हुए हैं. इस तरह के कामों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें हिंदू समाज की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने की मांग की है. शिकायत में बताया था कि कुछ अपराधी तत्व नौकरी दिलाने के नाम पर भोली-भाली हिंदू बेटियों और बहनों को झांसा दे रहे हैं. ये अपराधी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से अपना नाम बदलकर संपर्क करते हैं।

जल विजन 2047 पर राज्यों के जल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल

रायपुर। भारत सरकार के 'जल विजन 2047' के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केन्द्रीय राज्यमंत्री चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्रीगण मौजूद थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में जल प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि जनभागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल स्थान पर है। राज्य में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए दो लाख से अधिक संरचनाएं निर्मित की गई हैं। हम जिस राज्य छत्तीसगढ़ से हैं वह राज्य प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। वनों से अच्छांदित दण्डकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हैं। प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास का सर्वाधिक 10 साल छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए हैं। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है, यहां 44 प्रतिशत से अधिक भू-भाग में वन हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी और दक्षिणी भाग पठारी और वनों से अच्छांदित है। राज्य का मध्य हिस्सा मैदानी है। इस कारण राज्य में जल उपलब्धता असमान है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ जल नीति 2022 के तहत जल संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। भूजल अधिनियम 2022 लागू किया गया है और भूजल नियामक प्राधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई, पाइप सिंचाई नेटवर्क, जलग्रहण क्षेत्र विकास और जल-जगार अभियान को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गंगरेल डेम रविशंकर जलाशय से रायपुर और धमतरी की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।'जल विजन 2047' के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सिंचाई क्षमता 37.82 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। जल भंडारण 7900 मिलियन घन मीटर से बढ़ाकर 16,000 मिलियन घन मीटर तक ले जाना तथा औद्योगिक जल उपयोग 2208 मिलियन घन मीटर से 6000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाना है। पेयजल आपूर्ति 584 मिलियन घन मीटर से 2094 मिलियन घन मीटर तथा भूजल निकासी 5757 मिलियन घन मीटर से 8000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के आकाश ने रचा इतिहास

■ आकाश का राइफल शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन, इंडिया टीम के लिए हुआ चयन

रायपुर। जीवन में सफलता के लिए तय लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और लगन सफलता सुनिश्चित कराती है। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बी बी ए पंचम वर्ष के छात्र आकाश सराफ के लिए यह मूल मंत्र सच साबित हुआ है।रायफल शूटिंग के लिए जो जिद और जूनून उनके अंदर था उसी ने लगातार सफलता दिलाई है जिससे वे गोल्ड मेडल के लक्ष्य को हमेशा हासिल किया है।छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर आकाश ने भिलाई में अपनी उच्च शिक्षा के लिए एस एस पी यू को चुना।भिलाई में उनकी मुलाकात रायफल शूटिंग के प्रसिद्ध कोच नीरज निखिल सायमन से हुई और उनकी मुराद पूरी हो गई।नीरज सर के मार्गदर्शन में उन्होंने निशानेबाजी के सारे गुर सीखे।वे राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए दक्ष हो गए।

आकाश ने लगातार विभिन्न राष्ट्रीय और भारतीय टीम की चयन स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया।भोपाल की नेशनल रायफल शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और चयन स्पर्धाओं में अच्छा स्कोर किया।भोपाल में ही आयोजित नेशनल फाइनल के लिए तथा इंडिया टीम के लिए क्वालीफाई किया।आकाश बताते हैं मार्च 2025 में इंदौर में आयोजित होने वाली बिग बोर मैच के लिए वे तैयारी कर रहें हैं,उनका लक्ष्य अगस्त में होने वाले एशिया कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.